जीवन दर्शन

सफलता की खुशी मानना अच्छा है पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना -बिल गेट्स

दैनिक ग्लोबल हेराल्ड

LOCAL TO GLOBAL

महानगर संस्करण

www.globalherald.news

बुधवार 9 अप्रैल, 2025 ■ वर्ष 14 ■ अंक 57 ■ इंदौर-भोपाल से प्रकाशित ■ पेज 8 ■ मूल्य रु 2.00

कोलकाता घर में लगातार दूसरा मैच हारी:लखनऊ ने 4 रन से ...

पृष्ठ 8 पर

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ फूंका ट्रेड वॉर का बिगुल! अब वसूलेगा 104 फीसदी टैरिफ

नई दिल्ली ■

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को ऐलान किया कि 9 अप्रैल से चीन से आयातित वस्तुओं पर 104 फीसदी तक का अतिरिक्त टैरिफ वसूला जाएगा. यह कदम तब उठाया गया जब चीन ने अमेरिकी सामानों पर लगाए गए 34 फीसदी जवाबी शुल्क को हटाने से इनकार कर दिया.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट कहा कि चीन की जवाबी कार्रवाई एक भारी गलती थी. उन्होंने कहा, जब अमेरिका पर कोई वार करता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप और जोर से पलटवार करते हैं. यही वजह है कि अब चीन पर 104 फीसदी टैरिफ लागू हो गया है. हालांकि, अगर चीन बातचीत करना चाहता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप बेहद उदारता से उसका स्वागत करेंगे.

चीन को प्राथमिकता नहीं

ट्रंप प्रशासन के इस कदम से साफ है कि चीन अब अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में प्राथमिकता नहीं रखता. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अन्य देशों के साथ ट्रेड टॉक जारी रहेंगी, लेकिन चीन से किसी भी तत्काल समझौते की संभावना नहीं दिख रही. दरअसल, यह ट्रेड वॉर तब और गहरा गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को पहली बार टैरिफ बढ़ाने का संकेत दिया था. उस घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई थी, जिससे मंदी की आशंका और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ी उथल-पुथल की संभावना जताई गई. हालांकि, बाद में अमेरिकी बाजारों में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है.

चीन पीछे नहीं हटने वाला

दूसरी ओर, चीन ने भी आक्रामक रुख अपनाया है. उसने अमेरिकी टैरिफ को ब्लैकमेल बताते हुए कहा है कि वह अंत तक लड़ने को तैयार है. चीन के इस तेवर से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. इस टैरिफ वॉर का असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा. भारत जैसे विकासशील देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और निवेशकों की चिंता भारत के बाजारों को भी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में आने वाले समय में दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं इस आर्थिक लड़ाई से अछूती नहीं रहेंगी.

तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध

नई दिल्ली ■

तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल एक महीने के भीतर कदम उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोककर रखा है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी आरएन रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया।

कर्नाटक छेड़छाड़ मामला: गृहमंत्री ने माफी मांगी, कहा- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित

बेंगलुरु ■

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा,' मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं। अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं।'

जी परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे और तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही। दरअसल, बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके का है। घटना 3 अप्रैल की है। जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था- इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने राज्य गृह मंत्री की आलोचना की, और इस्तीफे की मांग की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जी परमेश्वर से इस्तीफा मांगना चाहिए।

वक्फ कानून आज से लागू:पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया

मुर्शिदाबाद ■

वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देशभर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था।

इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई है। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगी दी। इसके बाद भारी पुलिसबल मौके पर तैनात किया गया है। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अबतक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विधायकों में हाथापाई हुई

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी।

टीएमसी सांसदों के बहस के वीडियो शेयर किए

कल्याण बनर्जी-महिला नेता में बहस हुई, ममता का नेताओं को निर्देश- शांत रहें

नई दिल्ली ■

भाजपा आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने मंगलवार को टीएमसी सांसदों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की पार्टी की महिला नेता से बहस होती नजर आ रही है। मालवीय ने दावा किया कि यह घटना 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय में हुई। यहां टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने टीएमसी सांसदों के वॉट्सऐप ग्रुप 'एआईटीसी एमपी 2024' की चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे।

उन्होंने एक्स पोस्ट के कैप्शन में लिखा- चुनाव आयोग कैंपस में दो टीएमसी सांसदों के बीच विवाद के तुरंत बाद नाराज सांसद ने बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय महिला पर आरोप लगाना जारी रखा। ऐसा लगता है कि टीएमसी ने अपने सांसदों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव आयोग के पास जाने से पहले ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद कार्यालय में एकत्र हों।

शेख हसीना बोलीं- अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से बचाया

ढाका ■

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, ह्यअल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है। मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कठघरे में लाया जाएगा।ह्ल अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने यह बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपने पार्टी नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थीं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वे भारत में शरण लेकर रह रही हैं।

हसीना ने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशोआराम की जिंदगी जी। हसीना ने कहा कि उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे। लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वह अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है।

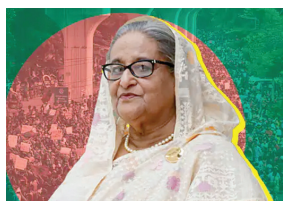

करण ओबेरॉय रेप केस में ट्रायल जारी रहेगा

सिंगर-एक्टर करण ओबेरॉय से जुड़े एक केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने पूजा बेदी समेत 8 लोगों की याचिका खारिज कर दी है। इन सभी पर शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि शुरूआती तौर पर आरोप सही लगते हैं, इसलिए केस अब ट्रायल तक चलेगा। ये मामला आईपीसी की धारा 228ए के तहत दर्ज हुआ है। इस धारा के मुताबिक, किसी भी रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है। करण के वकील दिनेश तिवारी ने कहा, 'मैं सिर्फ करण ओबेरॉय का केस देख रहा हूं, बाकी किसी आरोपी का नहीं।

राहुल बोले- हम दलित, मुस्लिम-ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया

अहमदाबाद ■

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा- हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है। मुद्दे उठाते रहना है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत है। यह हास्यास्पद है कि आज वह संगठन, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, उनकी विरासत का दावा कर रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आज भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर भी कब्जा कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया कि गांधीवादी और सहकारी आंदोलन के लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है।

भाजपा जानबूझकर नेहरू-पटेल को एक-दूसरे का विरोधी बताती है

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जिसका पिछले 140 वर्षों से देश की सेवा और लड़ाई का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने भाजपा-RSS पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के रूप में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह दिखाने की साजिश की कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच ऐसा रिश्ता था कि दोनों नायक एक-दूसरे के खिलाफ थे। सच्चाई यह है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे।

अमेरिकी यूट्यूबर बिना इजाजत भारत के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पहुंचा

भारत। भारतीय पुलिस ने 24 साल के एक अमेरिकी यूट्यूबर को हिंद महासागर के एक प्रतिबंधित द्वीप पर पहुंचने और वहां की जनजाति से संपर्क करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह यूट्यूबर अमेरिकी राज्य एरिजोना का रहने वाला है। उसका नाम मिखायलो विक्टोरोविच पोलियाकोव है। 29 मार्च को वह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पर पहुंचा था। वह वहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति से नहीं मिल पाया तो डाइट कोक और नारियल छोड़कर आया था। उसे 31 मार्च को पोर्ट ब्लेयर में गिरफ्तार किया गया था।

व्यंग्य : पैसे की माया : दोस्त दे दगा, दुश्मन कहे मैं सगा..?

'ना बाप बड़ा, ना भैय्या, सबसे बड़ा रुपय्या' यह कहावत पैसे की माया के कड़वे सच पर ही आधारित है और इसका प्रमाण अपनी दौलत की शक्ति से और अधिक महान बनने की अमेरिका के

ग्लोबल हेराल्ड न्यूज एनालिसिस GHNA

दिलीप शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टेरिफ नीति है और इससे ' दोस्ती ' शब्द ट्रम्प द्वारा दगा देने से तार तार हुआ है एवं भारत का दुश्मन चीन अब अपने को भारत का सगा बताने लगा है और यही सब तो पैसे की माया ही है, लेकिन इसमें जो चौकन्ना वही लाभ ले सकता है और भारत के लिए अवसर हैं कि सतर्कता से इस टेरिफ वार का फायदा ले..?

ट्रम्प का दोस्ती में दगा, चीन कहे मैं सगा : सचेत रहे मोदी सरकार और उठाए फायदा..?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती का दम भरने और अक्सर मोदी की तारीफ करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से दोस्ती के नाम पर छल किया है जिसका प्रमाण 26 फीसदी टेरिफ लगाना है. भारत ही नहीं 180 देशों पर टेरिफ लगाने वाले ट्रम्प के विरुद्ध 27 देश एकजुट हो गए हैं और ट्रम्प की 50 फीसदी अतिरिक्त टेरिफ की धमकी से परेशान चीन को भारत से दोस्ती याद आ गई है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से साथ देने की गुहार लगाई गई है. अब प्रधानमंत्री मोदी को सोचना है कि क्या 1954 में ' चीनी- हिंदी भाई भाई के नारे वाले उस चीन से कैसे सम्बन्ध रखना हैं, जिसने धोखा दिया और 1962 में युद्ध हुआ. उसके बाद से अक्सर छल कपट से अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत भारत की भूमि पर कब्जे की कोशिश में लगे चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि अमेरिका की दादागिरी से पार पाना है तो दोनों बड़ी आबादी वाले देशों को मिलकर अमेरिका को सबक भी सिखाने का वक्त आ गया है.उल्लेखनीय है कि भारत में चीन से भारी मात्रा में आयात किया जाता है और इम्पोर्ट के मुकाबले ड्रैगन को किए जाने वाले कम एक्सपोर्ट की वजह से भारत का चीन से 85 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है. ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने से भारत को भी चीन में निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ वॉर ने भारत और चीन को एक-दूसरे के करीब लाने का मंच सजा दिया है क्योंकि जहां अमेरिका की सख्त नीतियों ने दोनों देशों को नुकसान पहुंचाया वहीं इसने भारत-चीन दोस्ती को नया मौका दिया है. व्यापार बढ़ाने से लेकर सीमा विवाद सुलझाने तक दोनों देश अगर एक-दूसरे के साथ आते हैं तो आने वाला वक्त भारत और चीन की दोस्ती का बेहतर दौर हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपसी भरोसा और सहयोग को बढ़ाना होगा एवं चीन को छल - कपट त्याग आगे बढ़ना होगा तभी दोनों देश आपसी समझौते से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकते हैं..?

राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा

नई दिल्ली ■

एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल पार्टियों को 20,000 से ज्यादा के चंदों में सबसे ज्यादा भाजपा को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, BJP को मिला चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और माकपा को मिले कुल चंदे से 6 गुना ज्यादा है।

इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया है। इसमें बताया गया है कि देश की 6 नेशनल पार्टियों को 20,000 से ज्यादा के कुल 2,544.28 करोड़ के चंदे की जानकारी दी गई। इन नेशनल पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), आप, सीपीआई(एम) और एनपीईपी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 3755 डोनेशन कॉर्पोरेट या बिजनेस सेक्टर की तरफ से किए गए, जिनकी कुल रकम 2,262.5 करोड़ रही। यह कुल चंदे का 88.9% हिस्सा है। भाजपा को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट डोनेशन मिला।

मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 स्वीकृत

गौ-शालाओं में प्रति गाय 40 रुपए प्रति दिवस किये जाने का निर्णय

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025 की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढाने, किसानों की आय बढने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की निरन्तरता पर स्वीकृती दी गयी।

मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रुपए, सैंच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन वाली परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया हैं। इसे जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया हैं। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (सीपीएसई) संस्था है। संस्था के द्वारा म.प्र. में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा श्क कक्ष) के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल हैं।

नागरिकों की खुशहाली और बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत है आनंद विभाग

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

नागरिकों की खुशहाली एवं बेहतर जीवन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सकुशलता आवश्यक है। राज्य का पूर्ण विकास नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता से ही संभव है। नागरिकों के लिये इस प्रकार वातावरण तैयार करना होगा जो उनके लिए आनंद का कारक बनें। विकास का मापदण्ड भौतिक सुविधाओं पर आधारित होने के साथ-साथ नागरिकों के आनंद के आधार पर भी होना चाहिए। इस उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा आनंद संस्थान का गठन अगस्त 2016 में किया गया था। यह संस्थान, मध्यप्रदेश शासन के आनंद विभाग अन्तर्गत संचालित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान श्री आशीष कुमार ने बताया कि अपनी स्थापना के समय से ही राज्य आनंद संस्थान, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए सतत कार्यरत है। संस्थान का यह दृढ़ विश्वास है कि सुख बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभूति और एक स्वाभाविक अवस्था है, जिसे सही दृष्टिकोण, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी दिशा में कार्य करते हुए, संस्थान अपने विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और आनंदम गतिविधियों से नागरिकों में सकारात्मकता और आत्मिक आनंद की भावना विकसित करने का प्रयास कर रहा है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा विगत माह भोपाल में एक नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन चर्चा करना था। इस सेमिनार में देश के प्रमुख मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और नीति निमार्ताओं को आमंत्रित किया गया, ताकि वे अपने अनुभवों और शोध निष्कर्षों को साझा कर सकें। आयोजन ने आनंद के विविध आयामों एवं तत्वों पर केंद्रित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। सेमिनार में आतंरिक आनंद की अनुभूति, आनंद और स्वास्थ्य के बीच संबंध, खुशहाल परिवार एवं कार्य स्थल, विद्यार्थियों और युवाओं में मानवीय मूल्य को बढ़ावा देने की रणनीतियों और भारतीय परंपरा में आनंद के स्त्रोतों पर चर्चा की गई।

मोदी 11 को अशोक नगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम में पधार रहे

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम में पधार रहे हैं। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का भोपाल आगमन 13 अप्रैल को हो रहा है ।उनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे , साथ ही प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी । मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 12-13- 14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।

गड्ढे, खुले चैंबर, सड़कों की दरारें ले रहीं जान, न मुआवजा न ही जिम्मेदारों को सजा

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर में सड़कों की गलत डिजाइन, गड्ढों, खुले चैंबरों और दरारों से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कई नागरिकों की जान गई लेकिन इन हादसों में न तो कोई मुआवजा मिल रहा है न ही जिम्मेदारों को सजा हो रही है।

इंदौर में सड़क की दरारों, खुले चैंबरों और गड्ढों की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं लेकिन न तो किसी पीड़ित को कोई मुआवजा मिलता है न ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है। इन सभी मामलों में पीड़ितों की कहीं पर शिकायत भी दर्ज नहीं होती। पूरे देश में स्वच्छता के मामले में नंबर वन इंदौर सड़क हादसों के मामले में भी पूरे मप्र में नंबर वन है। साल 2024 में इंदौर में कुल 6,075 सड़क हादसे हुए हैं। 2023 में इनकी संख्या 5,714 थी। प्रदेश के अन्य शहरों की बात की जाए तो भोपाल दूसरे, जबलपुर तीसरे और ग्वालियर चौथे नंबर पर है। यहां क्रमशः 5,390, 4148, 3,092 सड़क हादसे हुए हैं। इंदौर में होने वाले सड़क हादसों में बड़ी संख्या उन हादसों की भी है जो सड़क की दरारों, खुले चैंबरों और गड्ढों की वजह से होते हैं। दो दिन पहले पलासिया क्षेत्र में हुए एक हादसे में एक महिला की जान जाने के बाद निगम जागा और तुरंत सड़कों की दरारें भरने के लिए काम शुरू कर दिया। वायएन रोड पर नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद आज सुबह तुरंत सड़कों की दरारों को भरा गया। इस तरह के हादसों के लिए सरकार, प्रशासन और नगर निगम के द्वारा किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। न तो जिम्मेदारों की लापरवाही तय होती है न ही पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है।

एजेंसी पर करेंगे कार्रवाई

नगर निगम की जनकार्य समिति के प्रभारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि चैंबरों के रखरखाव की निगरानी की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए बहुत जल्दी जीओ टैगिंग लागू की जाएगी। काम में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चैंबर की शिकायत मिलने पर एजेंसी को कार्रवाई करना होती है, अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो हम कार्रवाई करेंगे।

बढ़ते तापमान को देखते हुए लू (तापघात) से बचाव के लिए एडवायजरी जारी

इंदौर। इंदौर जिले में बढ़ते तापमान को देखते हुये लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवायजरी जारी की गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे लू (तापघात) से बचाव एवं उपचार हेतु एडवायजरी में दिये गये सुझावों का पालन करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.एस.सैत्या ने नागरिकों से अपील की है कि लू (तापघात) के लक्षण दिखाई देते ही निकट के अस्पताल में संपर्क कर आवश्यक दवा का उपयोग सुनिश्चित करें। लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव के उपाय करें। उन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में लू लगने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वृद्ध, बच्चे, खिलाड़ी, धूप में काम करने वाले श्रमिक सर्वाधिक खतरे में रहते हैं। पसीना न आना, गर्म-लाल एवं शुष्क त्वचा, मतली, सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, बेहोश हो जाना एवं पुतलियां छोटी हो जाना लू (तापघात) के प्रमुख लक्षण एवं संकेत हैं। गर्मी व लू से बचाव के लिए खूब पानी पीये व खाली पेट न रहें। शराब व चाय-कॉफी के अधिक सेवन से बचें।

धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर कमिश्नरेट में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये ऑनलाइन ठगी करने वाले की पहचान कर विधिसंगत कार्यवाही करते हुये उनकी धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निदेर्शों के अनुक्रम में ऑनलाइन ठगी की शिकायतों में क्राइम ब्रांच इंदौर की स्पेशल टीम को लगाया गया था।

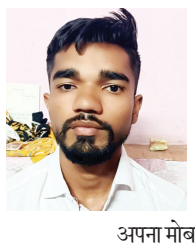

इसी अनुक्रम में फरियादी रमजान खान निवासी सांवेर रोड बाणगंगा के द्वारा शिकायत की गई थी जिसमें आवेदक ने बताया कि दिनांक 01/03/2025 में इंस्टाग्राम पर शुभम लौवंशी की आईडी पर नौकरी जाब से संबधित पोस्ट देखी थी जिस पर उसका मोबाईल नम्बर लिखा हुआ था मेरे द्वारा इस्टाग्राम पर चैटिंग की तो शुभम द्वारा मेरा मोबाइल नंबर मांगा जिसे मैने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था शुभम का काल मेरे पास उसी दिन रात मे आया और बोला की एसबीआई बैंक इंदौर में केवायसी की जाब है तो मैं भी राजी हो गया। अगले दिन दिनांक 02.03.2025 को मुझे शुभम ने राजवाडा पर बुलाया और बोला की अपना मोबाइल मुझे दो मोबाइल में कुछ वेबासाईट ओपन की फिर मेरा फोन वापस मुझे देकर बोला कि यह नम्बर लो इसमे एक रूपया ट्रासफर करा दो तो मैने फोन पे से एक रूपया ट्रासफर किया और बोला कि तुम्हारा अब रजिस्ट्रेशन हो गया बाद उसने मेरा मोबाईल वेबसाईट ओपन करने के नाम से लिया और मुझे पता ही नही चला कि उसने मेरे फोन पे के पासवर्ड देख लिये पीछे से उसने मेरे मोबाईल से स्केनर से 8200 रुपए और 5000 रुपए ट्रांसफर कर लिये उसके बाद एक अन्य खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किये तो अकाउन्ट पैसे नही होने के कारण फैल्ड बता दिया मुझे पता चला तो मैने बोला कि मेरे फोन से फोन पे क्यो किया तो मुझे डराने धमकाने लगा और बोला किसी को बताया तो अच्छा नही होगा और वहां से चला गया बाद मे मुझे पता चला कि इसने बहुत लोगो से इस तरीके से धोखाधडी कि गई जिसकी मेरे द्वारा आनलाईन शिकायत कि थी इस प्रकार शुभम लौवंशी द्वारा मेरे साथ 13,200/- रु की राशि धोखाधडी की गई।

नागरिकों का आवागमन कैसे सुविधाजनक हो इस पर रेल विभाग को गंभीरता पूर्वक विचार करना ही होगा-नारंग

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे मुख्य कार्यालय में पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में सलाहकार समिति सदस्य अजीत सिंह नारंग के प्रश्न के उत्तर में बताया गया की महू से मुख्तियार बलवाड़ा तक का गेज परिवर्तन का कार्य रेल विभाग अपने भरसक प्रयास करेगा कि यह कार्य वर्ष 2028अर्थात सिंहस्थ पूर्व तक पूर्ण हो जाए।

विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है एवं बस इंतजार है कि वन विभाग से कार्य करने हेतु भूमि उपलब्ध हो जावे। कुछ हिस्सों के टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं एवं कुछ हिस्सों के टेंडर आमंत्रित करने हेतु तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। इसी इसी प्रकार इंदौर धार छोटा उदेपुर होते हुए नवीन रेल मार्ग के बारे में बताया गया की गुजरात के हिस्से में कार्य पूर्ण हो चुका है क्योंकि उन्हें बहुत पहले ही वन विभाग से भूमि उपलब्ध हो गई थी लेकिन मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग से अभी तक वन विभाग द्वारा रेलवे को भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है अगर यहां पर भी भूमि उपलब्ध कराने हेतु अधिक समय नहीं लिया गया तो धार और छोटा उदेपुर के बचे हुवे हिस्से में रेल विभाग तुरंत टेंडर आमंत्रित कर इस रेल मार्ग को भी वर्ष 2028 तक पूर्ण कर लेगा। तात्पर्य यह है की इंदौर के आसपास जितने भी रेल मार्ग संबंधी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब उनकी प्रगति पूर्णतया वन विभाग द्वारा जल्द निर्णय लिए जाने पर आश्रित है। जब इंदौर की आबादी 10 लाख थी उस समय सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार चलने वाली गाड़ियां इंदौर के लिए स्वीकृत की गई लेकिन अब 40, लाख आबादी होने के पश्चात इन्हें नियमित करने की मांग परउत्तर देते हुवे कहा गया कि वर्तमान में इंदौर स्टेशन पर नियमित करने हेतु आवश्यक कई सुविधाओं का अभाव है। अजीत सिंह नारंग ने कहा कि ये सुविधाएं रेल विभाग को पूर्ण करना है और उसी की पूर्ण करने की जवाबदारी है। देश के सबसे तेज गति से बढ़ते शहर इंदौर में देश के सभी हिस्सों से आने वाले नागरिकों का आवागमन कैसे सुविधाजनक हो इस पर रेल विभाग को गंभीरता पूर्वक विचार करना ही होगा और नियमित करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे।

अजीत सिंह नारंग का महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा स्वागत करते हुए।

आशा से बनाएं जीवन को सुंदर...

फिर भी जिंदगी हसीन है...
dreamsachieverspune@gmail.com

जीवन में अक्सर लोग पुराने नकारात्मक अनुभवों को लेकर अक्सर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करना शुरू कर देते हैं। मेरी नजर में यह जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम अपनी क्षमता पर संदेह करने के स्थान पर प्रतिदिन छोटे-छोटे प्रयास करना शुरू कर दें तो यकीन मानियेगा हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दैनिक आधार पर की गई छोटी-छोटी कोशिशें हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए ही कहा जाता है कि हर छोटा कदम हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाता है।

निर्मल भटनागर (एजुकेशनल कंसलटेंट एवं मोटिवेशनल स्पीकर)
ग्लोबल हेराल्ड

इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा आगे देखो, अर्थात् जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपने देखो क्योंकि सपने हमें प्रेरित करते हैं; हमारे जीवन या हमें उद्देश्य देते हैं और जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू करते हैं तब आप अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानना शुरू करते हैं। इसके विपरीत जब हम सपने देखना बंद कर देते हैं, तो जीवन में ठहराव आ जाता है। इसलिए, हमेशा कुछ नया करने की आकांक्षा रखें और अपने सपनों को साकार करने का साहस दिखाएं और जैसा मैंने पूर्व में कहा था, इसके लिए प्रतिदिन प्रयास करें। याद रखियेगा दोस्तों, आशा वह ऊर्जा है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसके विपरीत जब आप खुद पर विश्वास करना छोड़ कर, प्रयास करना बंद करते हैं तब जीवन में आशा का अंत हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हर स्थिति-परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर आगे बढ़ें। ऐसा करना आपके जीवन में अनगिनत अवसर लेकर आएगा। शायद इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा अंग्रेजी के शब्द 'होप' का अर्थ 'हैव ओनली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन' बताया गया है। अर्थात् जीवन में केवल सकारात्मक उम्मीद रखें। यही बात दोस्तों, रिश्तों पर भी लागू होती है। अक्सर लोग छोटी-मोटी बातों का ज्यादा तवज्जो देकर अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं और सोचते हैं कि यह लोग जीवन भर कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इस नकारात्मक भाव की वजह से ही अक्सर हम अपने प्रियजनों की परवाह करना छोड़ देते हैं। सुधार की आस को नकारात्मक भाव के कारण छोड़ना रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है।लेकिन अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, आशा रख अपनी ओर से प्रेम का प्रदर्शन करेंगे तो पाएंगे कि रिश्तों में भी सुधार आ गया है। इसलिए ही कहा जाता है कि ÷जब हम एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो प्रेम न केवल जीवित रहता है, बल्कि और गहराई भी पाता है।÷ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ प्रेम का अर्थ केवल रोमांटिक भावनाओं तक सीमित नहीं है। दोस्तों, अगर आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सपने देखते रहें, आशा बनाए रखें और प्रेम करते रहें। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं या किसी का समर्थन करते हैं, तो आप न केवल उनका जीवन संवारते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। याने आप अपना जीवन भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए, जीवन में कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी कोशिशें छोटी हैं। प्रत्येक छोटी सी पहल भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हमेशा सपने देखें, आशा रखें और प्रेम को अपनी ताकत बनाएं। याद रखियेगा, यह जीवन वैसा ही है, जैसा इसे हम बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा सकारात्मक उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें और अपने आस-पास खुशियाँ बिखेरते रहें।

जल संरक्षण के संबंध में जन जागरूकता के लिए गाँव-गाँव हो रहे हैं जल संवाद

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के बारे में जन जागरूकता के लिए जल संवाद कार्यक्रमों का आयोजन गाँव-गाँव किया जा रहा है। जल संवाद कार्यक्रम में जहाँ एक ओर ग्रामीणों को जल की महत्ता बतायी जा रही है, जल बचाने का संकल्प दिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गाँव की जल संरचना के जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान भी किया जा रहा है।

इसी सिलसिले में गत दिवस जिले के देपालपुर विकासखंड के अनेक गाँवों में जल संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से हुए। इस दौरान जल संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जल संवाद कार्यक्रम सुमठा और अहिरखेड़ी में आयोजित हुए। जिसमें तालाब गहरीकरण हेतु सांकेतिक श्रमदान किया गया। धरती माता का पूजन किया गया। जल बचाने हेतु शपथ ग्रामीण जनों को दिलाई गई। विकासखंड समन्वयक श्री सुरेश चंद्र यादव ने कहा कि जल है तो कल है। पानी ओर पेड़ बचाने का प्रण लेना ही चाहिए। सरकार का संदेश गांव गांव तक पहुंचाने का काम जनअभियान परिषद कर रहा है। जन अभियान परिषद इसके माध्यम से गांव-गांव में गठित प्रस्फुटन समितियो के माध्यम से लोगो को जागरुक करने का काम कर रहे है। कार्यक्रम में सरपंच श्री रतनसिंह पंवार, प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह राठौर, श्री शोभाराम पंवार, श्री पदमसिंह, पर्यावरण प्रेमी श्री निर्भय सिंह गोयल, प्रस्फुटन समिति के सचिव श्री विशाल नागर ग्राम पंचायत के सचिव और ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

19 जून को सिकलसेल एनीमिया दिवस

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। नेशनल हेल्थ मिशन की संचालक डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में आज इंदौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कायक्रमों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इन्दौर, आलीराजपुर, बुरहानपुर, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं झाबुआ जिलों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में आर.सी.एच. सेवाओं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शहरी स्वास्थ्य कार्यकम, संजीवनी क्लीनिक की क्रियाशीलता, असंचारी रोग नियंत्रण, क्षय उन्मूलन कार्यक्रम तथा सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बेहतर एवं निम्न प्रदर्शन करने वाले जिलों से उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली गई।

सीएम हेल्पलाइन पर 17000 से ज्यादा शिकायतें, कलेक्टर आशीष सिंह की बढ़ी चिंता, अधिकारियों पर गिरेगी गाज

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर जिले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या अचानक 17000 के पार पहुंच गई है, हालांकि सुशासन और कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा की गई कई पहलें भी प्रभावी रही हैं। सामान्यतः हर महीने की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में शिकायतों के आंकड़े अचानक से बढ़ गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा बैठक बुलाई है। 50 दिन से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद 5000 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं और कलेक्टर आशीष सिंह अब उन विभागों पर कार्रवाई करने वाले हैं जिनकी सुनवाई में देरी हो रही है।

इंदौर जिले में शिकायतों का सबसे अधिक दबाव राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, परिवहन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम पर देखा जा रहा है। विशेष रूप से नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 4942 शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग में भी नए सत्र के दौरान 256 शिकायतें पेंडिंग हैं। कलेक्टर ने इन विभागों से संबंधित अधिकारियों को तलब किया है और 50 दिन से अधिक समय से लंबित 20 फीसदी शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है।

सी और डी कैटेगरी में आने वाले विभाग

सीएम हेल्पलाइन पर हर महीने 20 तारीख को शिकायतों की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कई विभागों का प्रदर्शन काफी खराब नजर आता है। इंदौर जिले के श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वन विभाग और सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग की रैंकिंग सबसे निचले स्थान पर रही है। इन सभी विभागों को डी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, सी कैटेगरी में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जनजाति कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वित्त विभाग, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और पुलिस विभाग शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उनके समाधान का प्रतिशत बहुत कम है।

समाधान ऑनलाइन प्रणाली और पेंडिंग शिकायतें

शासन के निर्देश पर सुशासन व समाधान ऑनलाइन प्रणाली को चलाया जा रहा है, लेकिन इस प्रणाली में भी 2155 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पाई गई हैं। राजस्व विभाग की खसरा ऑनलाइन अपडेट करने से संबंधित शिकायतें सिमरोल, मानपुर, और खुड़ैल क्षेत्र में अधिक पेंडिंग हैं। नामांतरण और बंटवारे से संबंधित मामलों में भी पेंडेंसी बढ़ी है, जिनमें बिचौली हप्सी, कैलोद करताल, मल्हारगंज और खुड़ैल में 10 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा, नल जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति ना होने के 110 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

40 सालों में चंदन नगर रिंग रोड नहीं बनी, अब चौड़ाई घटा कर लिंक रोड बनाने की तैयारी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

चंदन नगर से एरोड्रम रोड तक रिंग रोड नहीं बन पाने के कारण अधूरी रही। अभी भी भारी वाहन बड़ा गणपति क्षेत्र से गुजरते हैं। मास्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 200 फीट है। अब वहां इतनी बसाहट हो चुकी है कि इतनी चौड़ी सड़क बनाना संभव नहीं है। इसे देखते हुए नगर निगम ने रिंग रोड के बजाए अब चंदन नगर लिंक रोड बनाने का फैसला लिया है।

अब 200 फीट के बजाए 60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। इसमें सिर्फ 150 से ज्यादा निर्माण ही हटेंगे। नगर निगम के बजट में इस सड़क को भी मंजूरी दी गई है, ताकि लोग धार रोड से एरोड्रम रोड तक सीधे आ जा सकें। फिलहाल कालानी नगर से विजयश्री नगर ब्रिज तक 60 फीट चौड़ाई में सड़क बनकर तैयार है, लेकिन उसके आगे सड़क की चौड़ाई कहीं 30 तो कहीं 40 फीट है। अब नगर निगम बाधक हिस्से हटाकर 60 फीट चौड़ी सड़क बनाना चाहता है।

2008 में हो चुका था भूमिपूजन

वर्ष 2008 में चेंदन नेगर रिंग रोड बनाने की कवायद हो चुकी थी। तत्कालीन कलेक्टर विवेक अग्रवाल चाहते थे कि यह सड़क बन जाए। उन्होंने चंदन नगर क्षेत्र के रहवासियों को स्कीम-136 में प्लॉट भी अलॉट कर दिए थे। तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस सड़क का भूमिपूजन भी कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से सड़क बनाने की अनुमति नहीं मिली और फिर सड़क नहीं बन पाई। प्राधिकरण के अफसर नप्ती करने जाते थे तो उन्हें धमकाया जाता था। अब यह सड़क नगर निगम 18 मीटर चौड़ाई में बनाने की तैयारी कर रहा है। मास्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई बदलने के लिए प्रस्ताव भी भेजने की तैयारी की जा रही है मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि दो प्रमुख मार्गों की लिंक रोड के रूप में इस सड़क को बनाया जाएगा।

वक्ता बोले-वैकल्पिक मीडिया में निरंतरता जरुरी, तभी असीमित संभावना के आकाश खुलेंगे

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर प्रेस क्लब के पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन सफल होते वैकल्पिक मीडिया विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस मौके पर लखनऊ से आए पत्रकार संजय शर्मा ने कहा कि वैकल्पिक मीडिया एक बड़ी ताकत है। खबरों में स्थानीयता और अच्छा कंटेंट उसे आगे ले जा रहा है। इस माध्यम में निरंतरता जरूरी है,तभी असीमित संभावनाओं के आकाश खुले रहेंगे।

पत्रकार भुवनेश सेंगर ने कहा कि वैकल्पिक मीडिया में मेहनत ज्यादा है। स्थापित होने में समय लगता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलता है। यूट्यूब चैनल ठीक ठाक चल जाए तो खर्च निकल सकता है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मीडिया के कारण बड़े मीडिया संस्थानों के रेवेन्यू में कमी आई है। एआई आने के बाद मीडिया संस्थानों में नौकरियों के अवसर भी कम हो गए है। पत्रकार चंद्रभान सिंह ने कहा कि आपके कंटेंट में रोचकता होना चाहिए। ताकि पाठक को बांधा जा सके। वैकल्पिक मीडिया पर भरोसा जितना ज्यादा होगा, वह पाठक की उतनी बड़ी पसंद बनेगा। इससे ही पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ता है।

फोटो जर्नलिस्ट राजेश सिंह ने कहा,फोटो जर्नलिस्ट की जिंदगी मनरेगा मजदूर जैसी

दसरे सत्र में फोटोग्राफी पर कार्यशाला आयोजित की गई। ख्यात फोटोग्राफर राजेश सिंह ने कहा कि फोटो जर्नलिस्ट की जिंदगी मनरेगा मजदूर जैसी होती है। जिस दिन अच्छा फोटो हो जाता है उस दिन फोटो जर्नलिस्ट हीरो होता है, लेकिन दूसरे दिन फिर उसकी शुरूआत जीरो से होती है। फोटोग्राफर के लिए फील्ड ही सबकुछ है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर का प्रमोशन नहीं होता। वो जिंदगीभर फोटोग्राफर ही रहता है। परिचर्चा के बाद प्रेस क्लब द्वारा आयोजित फोटोग्राफी स्पर्धा के पुरस्कार भी बांटे गए।

अप्रैल में ही बरस रही आग, 40 डिग्री पार गया पारा

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

शहर के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि अप्रैल की शुरूआत इतनी गर्म रही है। सोमवार को सीजन और साल का पहला 40 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया। आम तौर पर, अप्रैल में तापमान में बढ़ोतरी 15 अप्रैल के बाद देखने को मिलती है, लेकिन इस साल यह शुरूआती दिनों में ही महसूस हो रही है। सोमवार को दिन का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। वहीं, रविवार को तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। रविवार की रात का तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को रिकॉर्ड किया गया तापमान इस साल का सबसे अधिक था और पिछले 10 सालों में से दो सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। इनमें 2020 में 16 अप्रैल को 39.7 डिग्री सेल्सियस और 2023 में 17 अप्रैल को 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान शामिल है। हालांकि, 2019 में अप्रैल का सबसे अधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड था। इस तरह, इस साल के तापमान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

गर्मी का प्रभाव लंबे समय तक रहने की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल की शुरूआत में ही इस प्रकार की गर्मी का होना इस बात का संकेत है कि इस बार गर्मी का असर पहले से ज्यादा तीव्र और लंबे समय तक रहेगा। हवाओं का रुख उत्तरी से बदलकर पश्चिमी हो गया है और आसमान साफ होने के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि शहर में गुरुवार तक गर्मी बनी रहेगी और इस दौरान तापमान 41 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। हालांकि, शुक्रवार से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी, जिससे शहरवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।

गुजरात की पटाखा फैक्टरी के ठेकेदार को इंदौर से पकड़ा, मप्र से भेजता था मजदूरों को

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्टरी के विस्फोट में पुलिस ने फैक्टरी मालिक को तो पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें ऐक ठेकेदार की भी तलाश थी। गुजरात पुलिस को पता चला था कि वह इंदौर के बिजलपुर क्षेत्र में रहता है। उसे गुजरात पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। इसके लिए इंदौर पुलिस ने भी मदद की।

आरोपी काम हरीश पिता रामचंद्र मेघवानी है। जब पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हुआ था, तब वह इंदौर में ही था, लेकिन फैक्टरी में हरीश ही मध्य प्रदेश से मजदूरों को भेजता था,जबकि उसे पता था कि फैक्टरी अवैध है। हरीश ने ही गोदाम के लिए स्थल को उपयुक्त बताया था। हरीश बिजलपुर क्षेत्र के ट्रेजर टाउन टाउनशिप में रहता था। हरीश पटाखा फैक्टरी के लिए मजदूर उपलब्ध कराता था और आर्थिक लाभ कमाता था। वह इंदौर में रहता था और देवास और हरदा जिले में जिन मजदूरों को पटाखे बनाने का अनुभव था, उन्हें वह गुजरात भेजता था। आपको बता दे कि गुजरात के बनासकांठा की पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के कारण 21 लोग जान गंवा चुके है और कुछ घायल भी है। इस मामले में पुलिस फैक्टरी मालिक खूबचंद मोहनानी और उसके बेटे दीपक को गिरफ्तार कर चुकी है।

अमरनाथ यात्रा के लिए इंदौर के13 अस्पताल में होंगे स्वास्थ्य परीक्षण

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

अमर नाथ यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है,जो यात्री अमर नाथ यात्रा के लिए जाना चाहते है, उनके लिए इंदौर में स्वास्थ्य परीक्षण की 13 अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। 14 अप्रैल से परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमर नाथ यात्रा पर 13 साल से बड़े बच्चे ही जा सकते है। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध यात्रा पर नहीं जा सकते है। इस बार यात्रा 38 दिनों की होगी और जुलाई के पहले सप्ताह में शुरूआत होगी।

इंदौर में सांवेर, देपालपुर, महू, मानपुर, हातोद में मेडिकल फिटनेस किए जाएंगे। इसके अलावा इंदौर में पीसी सेठी, हुकमचंद अस्पताल, मल्हारगंज, संयोगितागंज, नंदानगर,एमवायएच, लाल अस्पताल,पॉली क्लिनिक में स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अमरनाथ यात्रा जाने से पहले ब्लड टेस्ट, ईसीजी होगी। डॉक्टर यात्रा पर जाने वाले लोगों से मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। बीपी संबंधी बीमारी होने पर यात्रियों को समझाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम (ईसीजी) जैसी जांचे शामिल होगी। जांच होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट दिया मिल पाएगा।

कब्जे से परेशान बुजुर्ग दंपति सड़क पर लोट लगाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मंगलवार दोपहर का समय था और इंदौर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। इस भीषण गर्मी के बीच, एक बुजुर्ग दंपती अपने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उनका दर्द इतना गहरा था कि वे कलेक्टोरेट के मेन गेट से लेकर पोर्च तक लोट लगाते हुए पहुंचे। बाहर खड़े पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दंपती का कहना था कि अब बहुत हो चुका। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और वे किसी भी हालत में कलेक्टर से मिलने की जिद पर थे। दंपती ने बताया कि वे तेजाजी नगर के निवासी रामचरण बागवान हैं और पिछले दो सालों से उनका प्लॉट शेखर और गोलू नाम के दो युवकों ने जबरन कब्जा कर रखा है। उनका आरोप था कि जब भी वे विरोध करते हैं, ये युवक उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। दंपती ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाएंगे।

दो साल से परेशान दंपती की पीड़ा यह दंपती पिछले दो सालों से अपने अधिकारों के लिए चक्कर काटते-घूमते परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब उनका अंतिम उपाय यही है कि किसी तरह कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचकर अपनी बात रखी जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया कि वे अंदर जाकर अपनी शिकायत करें, लेकिन इस तरीके से नहीं।

मेरी टाइम दिवस पर डॉ (इंजीनियर)सांवरलाल शर्मा के उद्गार, समुन्दर सबसे बड़ा एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंस्टीटूशन ऑफ इंजीनियर भोपाल चैप्टर द्वारा ५ अप्रैल २०२५ को इंस्टीटूशन के केंद्र मे मेरी टाइम दिवस मनाया गया इस उपलक्ष मई मुख्य वक्ता के बतौर डॉ सांवरलाल शर्मा पूर्व नौसेना अधिकारी ने अपना समुन्दर ,अपनी जबाबदारिया एवं अपनी सामुद्रिक अवसर ,विषय पर बोलते हुए कहा की हमारी आर्थिक जोन को २०० सामुद्रिक माइल्स से बड़ा कर ३५० सामुद्रिक माइल्स के लिए भारत ने सयुक्त राष्ट्र मे आवेदन किया है सामुद्रिक ब्यापारिक रास्ते एवं समुद्र को मानवीय गंदगी, दुर्घटना से हुई गंदगी से तत्काल सुरक्षा की जरुरत है, सभी देशों को इंटरनेशनल मेरी टाइम आगेर्नाईजेशन के कानून को शक्ति से मानने के जरुरत पर जोर दिया। डॉ शर्मा कहते है की सागर अपने आप मे एक प्रकृतिक ट्रीटमेंट प्लांट है जो विश्व की सभी प्रकार की गंदगी को अवसादित करता है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है इस से सागर मे जीवन एवं पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा मिलती है सागर से ही पानी की प्राकतिक साइकिल को भी सम्बल मिलता है मेरी टाइम सिल्क रूट (हिन्द महा सागर ट्रेड रूट)जो चीन , दक्षिण एशिया , साउथ अफ्रीका ,अरब देश एवं मेडिटेरियन देशों से होते हुए सुएज नहर तक जाती है प्रधान मंत्री के सागरमंथन योजना के अंतर्गत भारत की ७५०० किलीमीटर की सामुद्रिक सीमा १२ बड़े बंदरगाह अवं २०० छोटे बंदरगाह की छमता को विकसित करना एवं भारत को ग्लोबल ट्रेड हब बनाना लक्ष है। इस अवशर पर भेल के जनरल मैनेजर श्री इंजीनियर प्रदीप उपाध्याय जी मुख्या अतिथि बतौर बोलते हुए सागर विज्ञानं पर प्रकाश डाला तथा इंस्टीटूशन ऑफ इंजीनियरस को हमेशा भेल का सहयोग देने का आश्वाशन भी दिया श्री राकेश राठोड कौंसिल मेंबर ने भारत के पुराने युग मे सामुद्रिक ब्यापार की चर्चा करी श्री इंजीनियर अशोक शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे मेरी टाइम दिवस की महत्ता की चर्चा करते हुए पुरातत्व युग मे सागर की महत्ता का उल्लेख किया श्री अशोक शर्मा ने भेल की तरफ से दिए गए सहयोग की सराहना भी की, श्री प्रदीप जी जनरल मैनेजर भेल का धन्यवाद् किया कार्य कर्म का संचालन अवं आभार संस्था के सचिव श्री इंजीनियर एके चौबे जी ने किया अतिथियों का स्वागत साल एवं श्रीफल से किया गया।

साइबर अपराधों से चाहते हो अगर बचना... तो हमेशा जागरूक रहकर सतर्कता का ध्यान रखना

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से, पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी अनुक्रम में अति. पुलिस उपायुक्त क्राइम इंदौर श्री राजेश दंडोतिया ने टीम के साथ देवाशीष अपार्टमेंट इंदौर में पहुंचकर, वहां उपस्थित करीब 80 रहवासियों को विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों की जानकारी दी और साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन-1930, पोर्टल इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 7049124445 आदि पर किस प्रकार शिकायत करें तथा पुलिस इन पर किस प्रकार कार्यवाही करती है आदि के संबंध में, प्रैक्टिकली समझाया। उन्होंने सभी से कहा कि वर्तमान में लगभग अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो गया है, और इस दौरान हमार कोई छोटी सी लापरवाही का भी दुरुपयोग कर साइबर क्रिमिनल्स नए-नए विभिन्न तरीको से साइबर फ्रॉड कर रहे है। इसलिए हम जागरूक और सतर्क रहकर पूरी सावधानी के साथ डिजिटल काम करें। यदि हम, फर्जी लिंक, फर्जी एप्स, फर्जी कॉल और फर्जी सोशल मीडिया चैनलों तथा प्रलोभन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म से बचे एवं अपनी निजी जानकारी किसी भी अनजान से शेयर ना करें तो, इन साइबर फ्रॉड से बहुत हद तक बच सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीम ने रहवासियों को साइबर अवेयरनेस के पम्पलेट्स व स्टिकर्स भी दिए और सभी को साइबर जागरूकता लाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया।

कमाल की इंजीनियरिंग

चिकित्सकों ने छोड़ा अपना चेम्बर, ओपीडी हॉल में बैठकर देखे मरीज

सतना ■

जिला अस्पताल के सर्जरी विभाग में सोमवार को एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। यहां 8 डॉक्टरों की टीम को केवल 8 फीट के ओपीडी चेंबर में बैठने की व्यवस्था की गई। यह कमरा इतनी छोटी जगह पर था कि मरीजों की संख्या के सामने यह व्यवस्था पूरी तरह से असमर्थ साबित हुई। नतीजतन, मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों को ओपीडी चेंबर छोड़कर अस्पताल के हॉल में कुर्सियां लगाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। जिला अस्पताल में सर्जरी विभाग के लिए जो ओपीडी कक्ष आवंटित किया गया है, उसकी चौड़ाई मात्र 8 फीट है। सर्जरी में सीनियर, जूनियर और इंटर्न मिलाकर 11-12 डॉक्टर होते हैं। सोमवार को जब करीब 8 चिकित्सक एक साथ पहुंचे तो उनके लिए एक साथ बैठना संभव नहीं था। इस कारण डॉक्टरों को हॉल में बैठकर ओपीडी का संचालन करना पड़ा, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा।

3 लाख का मेंटीनेंस, फिर भी अव्यवस्था

ओपीडी शुरू होने से पहले अस्पताल के इस हिस्से का 3 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग ने मेंटीनेंस कराया था। इसके बावजूद ओपीडी चेंबर की हालत दयनीय है। बिजली के बोर्ड टूटे हुए हैं। डॉक्टरों के वॉशरूम की व्यवस्था अधूरी है।

इधर, एमएलसी नहीं बनाने पर 5 बीएमओ को नोटिस

जिले के पांच विकास खंडों के बीएमओ को सीएमएचओ ने लापरवाही करने पर नोटिस जारी किया है। ये बीएमओ शासन के निर्देशों के बावजूद थानों को ऑनलाइन पोस्टमार्टम और एमएलसी रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे। इसका असर पुलिस अनुसंधान पर पड़ रहा था। राज्य शासन ने एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि थाने को अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर से मुक्ति मिले। इसके लिए मेडलीपर सॉफ़्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाती है। लापरवाही के कारण सीएमएचओ ने नागौद बीएमओ डॉ. प्रमोद प्रजापति, मझगवां बीएमओ डॉ. रुपेश सोनी, उचेहरा बीएमओ डॉ. एके राय, कोठी बीएमओ डॉ. अल्का माहुले और रामपुर बाघेलान बीएमओ डॉ. आरके सतनामी को नोटिस जारी किया है। सभी को 7 दिन में जवाब देने और लंबित रिपोर्ट 15 अप्रेल तक भेजने का निर्देश दिया गया है।

छह माह से फॉगिंग मशीनें बनीं शोपीस, शहर मच्छरों के कहर से बेहाल

कटनी ■

मच्छरों से बेहाल शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा खरीदी गई फॉगिंग मशीनें छह महीने बाद भी उपयोग में नहीं लाई गईं। लाखों रुपए की लागत से खरीदी गईं ये मशीनें नगर निगम परिसर में समग्र सेंटर के बाजू से धूल फांक रही हैं, जबकि शहर के 54 वार्डों में मच्छरजनित रोगों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

नगर निगम प्रशासन ने नवंबर-2024 में आधुनिक तकनीक वाली छह फॉगिंग मशीनें खरीदी थीं। ये मशीनें ई-रिक्शा पर आधारित हैं, जिससे उन्हें डीजल-पेट्रोल पर नहीं चलाना पड़ता और संचालन में लागत कम आती है। हर मशीन की कीमत करीब 4 लाख रुपये है। यानी कुल मिलाकर लगभग 24 लाख रुपए की राशि जनता के टैक्स से खर्च की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मशीनें नगर निगम परिसर से बाहर नहीं निकलीं। छह महीने बाद भी इनका संचालन शुरू नहीं हुआ है। मौके पर जाकर देखने पर

पता चला कि वहां अब केवल चार मशीनें मौजूद हैं। बाकी दो मशीनें कहां गईं, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नगर निगम के पास नहीं है। कटनी नगर निगम की यह लापरवाही न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। जिस उद्देश्य से ये मशीनें खरीदी गई थीं, वह पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन कब जागता है और इन मशीनों को वाकई जमीन पर उतारता है या फिर ये यूं ही शोपीस बनी रहेंगी।

पुरानी मशीनें भी गायब

नगर निगम के पास पहले से कुछ हस्तचालित फॉगिंग मशीनें भी थीं, जिनका इस्तेमाल विशेषकर बारिश के बाद मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उन मशीनों का भी कोई अता-पता नहीं है। उनका न तो इस्तेमाल हो रहा है और न ही रखरखाव की कोई व्यवस्था नजर आ रही है। ये मशीनें कबाड़ में पड़ी हैं।

जनता परेशान, अधिकारी बेपरवाह

शहर के विभिन्न वार्डों से मच्छरों की भरमार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे केस जिले में सामने आ चुके हैं। जिला अस्पताल में हर दिन एक हजार से अधिक की ओपीडी बीमारों होने वाले लोगों के आंकड़े बयां कर रहा है। मलेरिया, टायफाइड, डेंगू सहित कई रोगों के मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों में लगातार पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से फॉगिंग या मच्छरनाशक दवाओं का कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा।

जनप्रतिनिधियों को नहीं कोई सरोकार

जनता को सुविधा दिलाने के नाम पर विभागों के अफसर लाखों रुपए की फॉगिंग मशीनें, कीटनाशक सामग्री, डीजल-पेट्रोल आदि तो क्रय कराते हैं, लेकिन यह खेल सिर्फ कागजों में अधिकांश समय चलता है। शहर में मच्छरों के प्रकोप को कम करने कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि विभागों की बेपरवाही पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा।

लोगों ने बताई पीड़ा

राजा जगवानी, माधवनगर ने कहा कि हमारे वार्ड में पिछले कई महीनों से कोई फॉगिंग नहीं हुई है। कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। जब इतने पैसे की मशीनें खरीदी गईं तो फिर उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा। इसमें अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। विकास दुबे, तिलक कॉलेज ने कहा कि नगर निगम को जवाब देना चाहिए कि जब लाखों से से मशीनें खरीदी गईं तो चलवाई क्यों नहीं जा रहीं। साथ ही मशीनों को जल्द से जल्द वार्डों में भेजा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लापरवाही बरनते वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हो।

स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल

स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल है। लाखों रुपए कीमती की हस्तचलित फॉगिंग मशीनें खरीदी गई हैं। ब्लॉकों में भी सुविधा मुहैया कराई गई है। मलेरिया विभाग द्वारा इन मशीनों को शहर के वार्डों में चलाने, ग्रामीण इलाकों में कुआं कराने आदि को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही। सिर्फ अभियान के समय रस्म अदायगी की जाती है। जब डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, मलेरिया आदि बीमारी फैलती हैं तभी फोटो सेशन चलता है। शेष समय भले ही मच्छरों का प्रकोप रहे, मच्छर जनित बीमारियां, बढ़ें, लेकिन मशीनों से धुआं नहीं कराया जा रहा है।

सिंधी समाज का दर्दः सिंध से आए परिवारों को 77 वर्षों में भी नहीं मिला जमीनों का मालिकाना हक

कटनी ■

देश की आजादी के बाद 1948 में पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए सिंधी समाज के हजारों परिवार 77 वर्षों बाद भी जमीनों के मालिकाना हक से वंचित हैं। शहर के माधवनगर में पुनर्वास (नजूल) की भूमि पर ऐसे हजारों परिवार निवास कर रहे है जो सरकारों के लिए वोट बैंक बनकर रह गए हैं।

नगरनिगम के छह वार्डों के अंतर्गत काबिज इन करीब पांच हजार परिवारों से दोनों ही पार्टी के नेता वोट तो ले लेते है लेकिन इन परिवारों की सबसे बड़ी समस्या का हल अबतक नहीं हो चुका है। चुनाव में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक जमकर बैठकें कर

समाज को अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कहते है लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस समाज को भूला देते हैं। सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि 1972 से 1984 तक 1711 पट्टे बंटे थे। इसके बाद 1994 में 1200 लोगों ने आवेदन किया था, तभी से प्रकरण लंबित हैं। 2014-15 में सर्वे कराया गया था। उसमें यह तथ्य सामने आए थे कि पुनर्वास की जमीन में कुल 4 हजार 331 प्लाट हैं। पुनर्वास पट्टेदारों की संख्या 1711 है। रिक्त पड़े प्लाटों पर 1862 लोग काबिज हैं। रिक्त पुनर्वास भूमि पर 805 लोग काबिज हैं। इस तरह से कुल काबिजदारों की संख्या 2 हजार 667 है।

पुनर्वास की भूमि को कर दिया नजूल में दर्ज

जानकारी के अनुसार सरकार ने बीते वर्षों में पुनर्वास की भूमि को नजूल मद में परिवर्तित कर सिंधी समाज को भी धारणाधिकार योजना के तहत पट्टे देने की स्कीम लाई। 1 जून 2023 से 31 जुलाई 2023 तक इन परिवारों से आवेदन लिए गए। सरकारी की मंशा के आगे माधवनगर क्षेत्र के करीब 2260 परिवारों ने पट्टों के लिए आवेदन किया लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों में सिर्फ 27 लोगों को ही अफसरों ने पट्टा जारी किया। धारणाधिकार योजना में पात्र अधिभोगियों को प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके भू-खंडों के लिए 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किया जाना है।

जल गंगा संवर्धन अभियानः पाइप लाइनों के लीकेज सुधार एवं बावड़ी साफ सफाई का कार्य किया गया

सेंधवा (निर्मला वर्मा)। मध्यप्रदेश शासन के निदेर्शानुसार एवं कलेक्टर सुश्री गुंचा सनोबर के मार्गदर्शन में बडवानी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी एवं जनसहयोग से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को जनआंदोलन बनाना है। इसी क्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा घर-घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किया जा रहे पानी के अपव्यय को रोकने के लिए आवश्यक उपाय के तहत पाइप लाइनों की लीकेज सुधार संबंधी कार्य किये गये। साथ ही बड़वानी बस स्टैंड स्थित बावड़ी की साफ-सफाई का कार्य भी किया गया। उक्त कार्य में नगर पालिका परिषद बड़वानी के मैदानी अमले, कर्मचारियों एवं जनसहयोग के माध्यम से संपन्न कराया गया।

म.प्र. में नशा मुक्ति, भिक्षावृति उन्मूलन के लिये प्रयास है जारी : कुशवाह

देहरादून में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल हुए सामाजिक न्याय मंत्री

भोपाल ■

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देहरादून (उत्तराखण्ड) में दो दिवसीय भिक्षावृति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं नशा मुक्ति चिंतन शिविर में शामिल हुए। चिंतन शिविर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राज्यमंत्री द्वय श्री रामदास अठावले और श्री बीएल वर्मा तथा प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर सहित देश के अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंत्री श्री कुशवाह ने चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिक्षावृति उन्मूलन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के संबंध में बताया। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि देश को भिक्षामुक्त बनाने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट, शहरी स्थानीय निकाय एवं विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित कार्यवाही कर भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे है इसी कड़ी में प्रदेश के 7 धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक शहर-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, खण्डवा (ओंकारेश्वर), रतलाम एवं छतरपुर (खजुराहो) में स्माईल भिक्षावृति योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर के लिये उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021, बनाये जाकर 17 जून 2022 से प्रदेश में प्रभावशील है। प्रदेश में भारत सरकार के ट्रांसजेण्डर पोर्टल से 844 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के परिचय पत्र, प्रमाण पत्र जारी किये गये है इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान, पेंशन योजना, संबल योजना एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभांवित किया जा रहा है। मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में नशामुक्त अभियान में 50 हजार से अधिक सामुदायिक जनजागृति कार्यक्रम (कम्युनिटी अवयरनेस प्रोग्राम), 31 से अधिक ग्रामों में एवं 20 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को नशामुक्त भारत अभियान से जोड़ा गया है। देश में सर्वाधिक 11 हजार 500 से अधिक वॉलिटींयर्स पंजीकृत किये गये है तथा 4 लाख 20 हजार जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गई है।

सुहागरात के बाद थाने पहुंची पत्नी, बोली- मेरा पति नपुंसक

रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पत्नी ने थाने पहुंचकर अपनी ही पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह नपुंसक है। इसके साथ ही पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और प्रताड़ित करने सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है। दरअसल, पत्नी को जब पति की नपुंसकता के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नाराजगी जताते पति से सवाल किया कि झूठ बोलकर मेरी शादी क्यों करवाई। इसके जवाब देते हुए पति ने कहा कि ये बात किसी को मत बताना। महिला ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी दिसंबर 2024 में हुई थी।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रीकिय विभाग
मैकेनिकल खण्ड, इंदौर,
फेक्स नं. 2459300 फोन नं. 24516230-mail-eephemindore@gmail.
क्रमांक 369 / तक / का.यं. / मेके. खंड, / 2025 इंदौर दिनांक 05/05/25

विषय अनुपयोगी एवं पुरानी सामग्री विक्रय
हेतु ऑनलाईन निलामी आमंत्रण सूचना क्रमांक 02 / 2025-26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम निम्नानुसार स्टोर एवं मशीनरी के अनुपयोगी एवं पुरानी सामग्री के निलामी हेतु प्रपत्र जी का ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड इंदौर द्वारा निम्न विवरण अनुसार स्टोर एवं मशीनरी के अनुपयोगी एवं पुरानी सामग्री कि नीलामी हेतु ऑनलाईन में आरक्षित मूल्य से उच्चतम मूल्य प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन खुली निलामी आमंत्रण की जाती है।

सामग्री	विवरण
निलामीकर्ता	Office of the Executive Engineer P.H.E. Mechanical Division Indore.
E- AUCTION DATE	21-04-2025
AUCTION START TIME	10.30 AM
AUCTION END TIME	17.30 PM.
NO. OF EXTENSIONS	Unlimited
DURATION OF EACH EXTENSION	10 Minutes
INSPECTION	11.00 upto 17.00 (04/04/25 to 17/04/25)
Scrap and unusable material LOCATION	Office of the Assistant Engineer P.H.E. Mechanical Sub-Division, Dhar, Behind Collectorate Office Dhar
UPSET PRICE	Rs. 615000/-
EMD	Rs. 12300/-
LAST DATE OF SUBMISSION	Date 18/04/2025 Time 17-30
E- AUCTION NO	2025_PHED_80

G-11310/25

Executive Engineer
P.H.E.D. Mech Division
Indore

■ दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ना बैठाएं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
■ देर से घर आए लेकिन दुरुस्त आए, धीरे चले सुरक्षित चले।

ट्रम्प की ईर्ष्या अब बनेगी वैश्विक ट्रेड वार ..!

ट्रम्प के मन में टैरिफ को लेकर आया विचार एकाएक नहीं है। उनके व्यवसाय को जापानियों से मिली चुनौतियों के चलते 1990 के दशक में की घटना है जिससे क्रुध्द ट्रम्प आज पलटवार कर रहे हैं। यह अर्से से उनके मन में पाला हुआ मंसूबा है। वास्तव में ट्रम्प के मन में जापानियों की प्रतिभा को लेकर पनपा ईर्ष्याभाव ही आज उनके टैरिफ की असल वजह है। वो मानते हैं कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व में नहीं था तब जापान, अमेरिका के बाजार में जबरदस्त पैठ बना रहा था। लेकिन अपने यहां व्यापार करना असंभव सा कर दिया था। बस यही टीस बिजनेसमैन ट्रम्प को घर कर गई और उनके मन में एक गांठ बन गई। हालांकि उसी दौर में उन्हें नगदी की जबरदस्त जरूरत हुई और मजबूरन जापान की ओर आस भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन ट्रम्प 1980 के दशक से ही इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मशहूर जापानी निवेशक रॉकफेलर अमेरिकी ब्रांड्स और संपत्तियों के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनका नजरिया ऐसा बदला जो आज आयात पर टैरिफ के सच के रूप में सामने है। यहीं से उनके दिमाग में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मंसूबा भी बना और वो लंबी रणनीतियों और विचारों को लोगों से सार्वजनिक मंच पर जाहिर भी करने लगे।

ऋतुपर्ण दवे
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

1987 में ट्रम्प की किताब ट्रंप- द आर्ट ऑफ द डील में अमेरिकी व्यवसाय पर उनकी विस्तृत सोच के साथ मंशा भी झलकती है। लोकप्रिय द ओपरा शो के होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ भी तभी एक लाइव कार्यक्रम में साफ-साफ कहना कि अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को वो कैसे सबसे अलग तरीके से संभालेंगे और इससे अमेरिका के लिए सही कीमत वसूलेंगे उनका रणनीतिक शो था। इतना ही नहीं ट्रम्प ने अपने विचारों को एक खुली चिट्ठी के रूप में अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में भी बतौर विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें उनके एक लाख डॉलर खर्च हुए थे। मतलब उनका नजरिया पहले ही साफ हो चुका था। लेकिन यह भूलना चाहिए कि उनकी सोच और वास्तविकता में तब और अब में काफी फर्क है। आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी चीन है न कि जापान। 1990 के दशक के युवा रियल एस्टेट डेवलपर ट्रम्प की सोच आज भी वही है जबकि समय के साथ काफी कुछ बदल गया है। लेकिन ट्रम्प हैं कि मानते नहीं। बतौर राष्ट्रपति और व्यवसायी ऐसी सोच अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकती है। जैसा कि झलक रहा है इससे अमेरिका में विदेशी व्यापारिक निवेश घटेगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। सौ देशों की अमेरिकी डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ वाली सूची में भारत भी शामिल है जिस पर 26 प्रतिशत टैरिफ है जो कई एशियाई देशों की तुलना में कम है। भले ही भारत पर इसका प्रभाव अभी कम पड़े। लेकिन भविष्य को लेकर कोई गारंटी भी तो नहीं कि कब और कितना बढ़ जाए? इधर चीन ने भी अमेरिका पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। जिस पर तिलमिलाए ट्रम्प ने 9 अप्रेल तक

इसे वापस नहीं लेने पर 50 प्रतिशदत टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। इधर ब्लूमबर्ग की हालिया सूची बताती है कि ट्रंप के करीबी मस्क की कुल नेटवर्थ 300 अरब डॉलर के नीचे चली गई है। जनवरी 2025 से अब तक 135 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। इसी सोमवार को अमेरिकी बाजार में आई गिरावट से मस्क को करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि बीते हफ्ते दो दिन में ही मस्क के 31 अरब डॉलर डूब गए। इस तरफ ट्रम्प के अघोषित टैरिफ वार से विश्व में सबसे नुकसान उठाने वालों की सूची में मस्क 6वें क्रम पर आ चुके हैं। कुल मिलाकार आसार अच्छे नहीं है। नए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1,88,754 करोड़ तथा किसान कल्याण के लिए बीते बरस की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा यानी 1.71 लाख करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान बताता है कि हमारी अपने आर्थिक मोर्चों पर कैसी तैयारी है। भले ही 02 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने अमेरिका का मुक्ति दिवस बता रहे हों। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हुए, उससे कुछ अलग ही समझ आ रहा है। ट्रम्प भले ही कहें कि हमारे करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला आदेश उनकी ईर्ष्या, खीझ और अजीब दूरगामी सोच ही दशार्ता है। अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय यूनियने के टैरिफ के लिए 9 अप्रैल का इंतजार करना होगा, जिस पर मतदान होना है। यदि यह भी जस का तस जैसे रहा तो आसार और बिगड़ सकते हैं। पहले ही दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं। खुद अमेरिका भी इसी से अछूता नहीं है। ट्रम्प का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। उन्हे न केवल तानाशाह बल्कि अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने वाला सनकी तक कहा जाने लगा है। सभी 50 राज्यों में 150 संगठनों 1200 से ज्यादा प्रदर्शनों में हजारों का जुटना बताता है कि चिंता कितनी गंभीर है। हैंड्स ऑफ नाम के इस प्रदर्शन में शनिवार को हजारों लोग जुटे। 2017 में महिला मार्च और 2020 में ब्लैक लाइव्स आन्दोलन के बाद ट्रंप का ऐसा भारी विरोध हो रहा है। असल में एलन मस्क का दखल भी अमरीकियों को पसंद नहीं आ रहा है। उन पर नौकरी में छंटनियों के मंसूबों सहित सत्ता हथियाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर भारत और खुद अमरीका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज खुलते ही जबरदस्त तो कहीं ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है व्यावसायिक हितों और तमाम दूसरे मामलों में सतर्क दुनिया ने एकजुट होकर ट्रम्प को जवाब देना शुरू कर दिया है जिससे वैश्विक ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। काश ऐसा नहीं होता और ट्रम्प समझदारी और विवेक से काम लेते। दुनिया में कम से कम खुशहाल इंसानियत के लिए तो सौदेबाजी से बचा जाए। लेकिन ट्रम्प नहीं माने और बदली हुई परिस्थितियों में बाकी सभी एकजुट हो आपदा में अवसर तलाशने लगे तो कहीं अमेरिका ही हासिए पर न चला जाए? अच्छा होता कि इतना तो ट्रम्प समझ पाते!

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पहले होती जांच तो बच सकती थी 7 लोगों की जान

दमोह ■

मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम उर्फ डॉ. नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र की टाउनशिप में छिपा बैठा था। दमोह साइबर सेल ने उसका मोबाइल चालू होते ही लोकेशन ट्रेस कर दबोचा है। पुलिस आरोपी को रात 11.30 बजे दमोह लाई थी। वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंची और ऑपरेशन के चलते जान गवाने वाले 7 मरीजों के परिजन के साथ-साथ बचने वाले एक मरीज के परिजन के बयान दर्ज कराए। वहीं, कलेक्टर, एसपी व सीएमएचओ के बयान भी लिए गए।

इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल से भी फर्जी डॉ. के संबंध में बातचीत

की। क्योंकि, इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की भी एंजियोप्लास्टी की थी। बेटे प्रदीप शुक्ल को संदेह था कि, उसी के बाद हालत बिगड़ने के कारण उनके पिता की मौत हो गई थी। मानवाधिकार आयोग द्वारा लिए गए पीड़ित परिजन के बयानों और राजेन्द्र शुक्ल के बेटे से हुई बातचीत से ये प्रतीत हुआ है कि, अगर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के खिलाफ पहले ही जांच कर ली जाती तो शायद आज उन 7 लोगों की जान किसी फर्जी डॉक्टर के हाथों न जाती।

फर्जी डॉ. ने बताए तीन, पर असल में दो ब्लाकेज थे- पटेल

दमोह में मानवाधिकार आयोग को बयान दर्ज कराने दमोह के सिविल वार्ड निवासी कृष्णा पटेल भी आए। डॉ. एन जॉन केम ने जिन 8 मरीजों का इलाज किया था, उनमें से इस युवक के दादा ही बचे थे। 31 जनवरी को कृष्णा अपने दादा आशाराम पटेल को लेकर मिशन अस्पताल पहुंते थे। वहां, कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम ने उन्हें तीन ब्लॉकेज बताते हुए ओपन हार्ट सर्जरी कराने को कहा। लेकिन, जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो भड़क गए। हालांकि, उन्होंने वहां सिर्फ दादा की एंजियोप्लास्टी ही कराई थी। डॉक्टर से संतुष्ट न होने के चलते जब उन्होंने बाहर ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए डॉ. केम से एंजियोप्लास्टी की सीडी मांगी तो उन्होंने पहले तो देने से इंकार कर दिया। बमुश्किल उन्हें सीडी दी तो पता चला कि वो सीडी खाली थी। इसके बाद जबलपुर में जांच कराई तो पता चला कि दादा के तीन नहीं दो ब्लॉकेज निकले। पटेल ने बताया, डॉ. केम पहले नरसिंहपुर के एक निजी अस्पताल में था, जहां भी तीन लोगों की इसी तरह इलाज के दौरान मौतें हुई थीं। पटेल ने बताया कि, फरवरी में उसने कलेक्टर को इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। उस दौरान जांच का आश्वासन तो मिला था, पर बाद में कोई अपडेट ही नहीं दिया गया।

मुझे मुआवजा नहीं डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई चाहिए

नबी कुरैशी ने मानवाधिकार टीम को मां रहीसा बेगम के इलाज के दस्तावेज दिए। टीम ने पूछा- क्या चाहते हो। नबी ने कहा, मुआवजा नहीं चाहिए। मां को नहीं बचा सका, पर उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सख्त कार्रवाई होगी। कोई कमी, गलती या तथ्य छिपाए हैं तो सरकार संज्ञान लेगी। सीएम ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को गहन जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व विस अध्यक्ष के बेटे प्रो. प्रदीप की जुबानी

बिलासपुर में बातचीत के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल के बेटे प्रोफेसर प्रदीप शुक्ल ने बताया कि, 2 अगस्त 2006 की बात है। मेरे बाबूजी राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की तबीयत खराब होने पर शहर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहां बाबूजी का इलाज डॉ. राजीव राठी करते थे। लेकिन, वे अपोलो छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उनकी जगह डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव ने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी। उस समय डॉ. नरेन्द्र के बारे में बताया गया था कि, वे मध्य भारत में लेजर से हार्ट का ऑपरेशन करने वाले सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। सर्जरी के कुछ घंटे के बाद बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें करीब 18 दिन तक वेंटीलेटर पर आईसीयू में रखा गया। लेकिन प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करते ही 20 अगस्त 2006 को बाबूजी नहीं रहे। प्रो. प्रदीप शुक्ल ने आगे कहा- तभी मुझे डॉ. विक्रमादित्य पर शक हुआ था। इसके बाद अपोलो में भी इस डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी के बाद कुछ और मौतों की खबरें सामने आई थी। अपोलो का स्टाफ भी इस फर्जी डॉक्टर को पसंद नहीं करता था। वो यहां अकेला रहता था। इस बीच डॉ. नरेन्द्र अपोलो से फरार हो गया। उस दौरान मैंने आरटीआई लगाकर उनकी डिग्री की जानकारी मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं दी गई। मैं उन्हें गूगल आदि पर ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब दमोह मिशन हॉस्पिटल में 7 मौतों के पीछे इस डॉक्टर का नाम और फोटो सामने आया तो मेरे सामने 2006 का वो दृश्य आ गया। काश, उस समय फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जॉन केम के खिलाफ कड़ी जांच हुई होती तो आज दमोह समेत इतनी जगहों पर इस तरह मौतें नहीं हुई होतीं। ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

पानी से फिर लबालब होगी एमपी की 427 किमी लंबी नदी, 44 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी सूरत

भोपाल ■

भीषण गर्मी के कारण जब मार्च-अप्रेल में ही नदियां सूखने लगी हैं तब यह खबर लोगों को राहत दे सकती है। मध्यप्रदेश में नदियों को सूखने से बचाने और सालभर पानी से लबालब बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कई जतन कर रही है। इसके लिए नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है जिससे प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका हमेशा के लिए जलसंकट से मुक्त हो जाएगा। कुल 44 हजार 605 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से एमपी में बुंदेलखंड के 10 जिलों को भरपूर पानी मिलेगा।

करीब 24 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैले बुंदेलखंड की केन और बेतवा दो सबसे बड़ी नदियां हैं। इसके बावजूद इलाके में जल संकट बना रहता है। इसे दूर करने के लिए केन और बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ने की परियोजना पर काम चल रहा है। 427 किमी लंबाई में बहती है केन केन नदी का उद्गम मध्यप्रदेश के कटनी ज़िले में विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला में है। पन्ना में इससे कई धाराएं आकर जुड़ती हैं। यूपी के बांदा ज़िले में यह यमुना से मिल जाती है। इस दौरान केन, दोनों राज्यों में करीब 427 किमी का सफर तय करती है। केन को बेतवा से जोड़ने से पानी की बबार्दी पूरी तरह रुक जाएगी। केन नदी सालभर पानी से लबालब बनी रहेगी।

230 किमी लंबी नहर से जुड़ेंगी केन और बेतवा नदियां

प्रोजेक्ट में छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। यह बांध खजुराहो के पास पन्ना जिले की सीमा पर केन नदी पर बनाया जाएगा। दौधन बांध से 230 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। एमपी के निवाड़ी में केन और यूपी के झांसी जिले की सीमा पर ओरछा के करीब बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा।

एमपी के 10 जिले होंगे लाभान्वित

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से एमपी के 10 जिले- निवाड़ी, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। यूपी के भी 4 जिलों में पानी पहुंचेगा। दोनों राज्यों के 9.5 लाख किसानों की 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी। इसके साथ ही 62 लाख लोगों के लिए पेयजल का संकट भी समाप्त हो जाएगा।

गुब्बारे ने ली 8 माह के बच्चे की जान, सदमे में परिजन

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गुब्बारे ने आठ माह के बच्चे की जान ले ली। मासूम ने खेलते समय गुब्बारा निगल लिया, जो उसकी श्वास नली में फंस गया। डॉक्टरों ने गले में फंसा बैलून तो निकाल दिया लेकिन उसकी जान बचाने में असफल रहें। इस घटना से आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया। ये दर्दनाक घटना शिवपुरी जिले के नए बस स्टैंड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, बस स्टैंड के पास रहने वाले संजय सोनी के आठ माह के बेटे की मौत एक गुब्बारा निगलने से हो गई। रविवार को बच्चे ने घर में पड़ा गुब्बारा निगल लिया, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मामले की जानकारी होते ही परिजन मासूम को निजी अस्पताल लेकर गए।

नगर की काकड़ अंतिम विश्राम को भी आगे ले जाने की योजना नपा ने बनाई

सेंधवा (निर्मला वर्मा)। रोड निर्माण के चलते व नगर की आबादी से बसावट फैलने से पूर्व में बने अंतिम विश्राम का ओटला को वहां से हटा कर आगे लेजाया जाएगा। जो वर्तमान में अस्थाई होकर रोड निर्माण के बाद जगह का चयन होकर स्थाई ओटला का निर्माण किया जाएगा।

नपा से प्राप्त जानकारी अनुसार शव के अंतिम संस्कार हेतु मुक्तिधाम ले जाने से पहले नगर की काकड़ (नगर की सीमा) पर अंतिम विश्राम होता है। जिसमें शव की अर्थी को रख कर कोई पिंड दान कर कंधा बदले की प्राचीन परंपरा रही है। जिसके चलते सेंधवा में अम्बेडकर कालोनी के अंतिम छोर पर अंतिम विश्राम का ओटला निर्मित है। नगर के विकास व सौंदर्य करण हेतु पुराने एबी रोड को मुख्यमंत्री अधोसंरचना व कायाकल्प योजना के तहत सेंटर डिवाइडर युक्त सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण हो रहा है। नगर की बसावट व बढ़ती आबादी को मध्यनजर रखते हुए नगर की काकड़ अंतिम विश्राम को भी आगे ले जाने की योजना नपा ने बनाई है। चुकी अभी स्थाई काकड़ के लिए जगह का चयन नहीं होने व रोड निर्माण के दौरान एक साइट से यातायात का दबाव होने से बीच में अंतिम विश्राम के ओटले को आज बुधवार को हटाया जाकर अस्थाई अंतिम विश्राम का ओटला मप्र विद्युत मंडल के ग्रिट व नेशनल हाईवे लोक निर्माण की भूमि के सेंटर पर अस्थाई रूप से लगाया जा रहा है। अस्थाई होने से वर्तमान में यह ओटला लोहे का बनाया गया है जो तगहत के रूप में होगा। इसके नपा सीएमओ मधु चौधरी, उपयंत्री सचिन अलुने, प्रवक्ता सुनील अग्रवाल ने अस्थाई ओटले के लिए नपा अध्यक्ष बसंती बाई यादव के निर्देश पर उक्त स्थान का चयन किया गया है। उक्त ओटला 7 बाय 4 का होगा। रोड निर्माण के पश्चात अंतिम विश्राम के ओटले की जगह का चयन होकर इसे पक्का व सुंदर बनाया जाएगा। वही मुक्तिधाम में लगे वाटरफॉल जो कापी समय बना हुआ है किंतु उसका उपयोग नहीं होने से अब उसके सौंदर्य करण पर भी विचार किया गया है।

सोशल मीडिया पर मिलने वाले लिंक से सावधान !

भोपाल ■

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल में ही बीते दो साल के दौरान 32 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में निवेश के नाम पर ठगी के अब तक 377 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। शहर में साल 2023 से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की शुरूआत हुई थी और 2024 में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं, 2025 में फरवरी महीने तक ही 23 मामले सामने आ चुके हैं। साइबर एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर मिलने वाली लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है।

साल 2023 में राजधानी में 95 मामले दर्ज हुए, जिसमें कुल 1 करोड़ 88 लाख की ठगी की जानकारी सामने आई। वहीं, साल 2024 में 259 केस दर्ज हुए,

जिनमें 27 करोड़ 15 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज हुई। वहीं, साल 2025 के फरवरी महीने तक ही 23 मामले दर्ज हुए, जिनमें 3 करोड़ 65 लाख की ठगी की बात सामने आ चुकी है। इस तरह साल 2023, 2024 और 2025 के सिर्फ दो माह में 377 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 32 करोड़ 69 हजार की राशि ठगी गई है।

साइबर एक्सपर्ट की सलाह

लगातार बढ़ रहे ठगी के मामलों को लेकर साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी ने आम लोगों को सलाह दी है कि, ऑनलाइन निवेश कंपनियों के संपर्क में न जाएं, सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियों के जरिये ही निवेश करें। शुरू में फायदा दिखा कर लोगों को फंसाया जाता है। फायदा देख कर लोग भी बड़ा निवेश कर देते हैं।

लोगों में जागरुकता ही ठगी से बचाएगी

इस संबंध में भोपाल एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि, पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अवेयरनेस कार्यक्रम की वजह से लोग जागरूक हुए हैं और निवेश के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड में कमी भी देखने को मिली है।

8 से 20 प्रतिशत तक का ग्रोथ दिखाया ठगे 25 लाख

इस मामले में एक व्यक्ति के साथ 25 लाख की ठगी की गई है। फरियादी ने बताया कि जालसाज ने खुद को अमेरिकी निवेश कंपनी का यूनिट का हेड बताकर निवेश करवाया जिसमें उन्हें 20 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई गई। फिर एक ऐप के माध्यम से निवेश करने पर 8 से 20 प्रतिशत तक का ग्रोथ दिखाया। जालसाजों ने पहले 7 लाख और फिर 20 लाख रुपए निवेश करवाया जिसमें ग्रोथ 1 करोड़ तक दिखाई गई, लेकिन जब फरियादी ने पैसे निकालने की कोशिश की तो पैसे नहीं निकले।

जंगलों पर छाया इंसानों का आतंक: एक अनदेखा संकट

हाल ही में एक प्रमुख अखबार की हेडलाइन ने ध्यान खींचा–शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक। यह वाक्य पढ़ते ही एक गहरी असहजता महसूस हुई। शायद इसलिए नहीं कि खबर गलत थी, बल्कि इसलिए कि वह अधूरी थी। सवाल यह नहीं है कि जानवर शहरों में क्यों आ गए, बल्कि यह है कि वे जंगलों से क्यों चले आए? हम जिस आतंक की बात कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रकृति का प्रतिवाद है–उस दोहरी मार का नतीजा जो हमने जंगलों और वन्यजीवों पर एक लंबे अरसे से चलाया है। विकास के नाम पर हमने जंगलों को काटा, नदियों को मोड़ा, और पहाड़ों को तोड़ा। वन्यजीवों के लिए न तो रहने की जगह छोड़ी, न भोजन का साधन। जब उनका प्राकृतिक निवास उजड़ गया, तब वे हमारी बस्तियों की ओर बढ़े। और अब, जब वे हमारी छतों, गलियों और पार्कों में दिखते हैं, तो हम उन्हें ह्यआतंकीह्न करार देते हैं। यह नजरिया न केवल नैतिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि हमारी नीति और प्राथमिकताओं में गहरी खामी को भी उजागर करता है। विकास और संरक्षण को एक-दूसरे के विरोधी खेमों में खड़ा कर देने का नतीजा यह है कि न तो सही मायनों में विकास हो पा रहा है, न ही प्रकृति का संतुलन बच पा रहा है।

-प्रियंका सौरभ
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

हाल ही में एक अखबार की प्रमुख हेडलाइन पढ़ी–शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक। यह वाक्य महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके का प्रतिबिंब था। हमने जानवरों के शहर में आने को आतंक करार दिया, लेकिन कभी यह सवाल नहीं पूछा कि वो शहर में आए ही क्यों? जब कोई बंदर किसी कॉलोनी की छत पर उछलता है, या कोई कुत्ता कूड़े के ढेर में भोजन तलाशता है, तो वह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। यह उस संकट का संकेत होता है जिसे हम–मनुष्य–ने स्वयं गढ़ा है। जंगल, जो कभी इन जीवों का घर थे, अब रियल एस्टेट की परियोजनाओं, खनन कार्यों, सड़कों और डैमों की बलि चढ़ चुके हैं। आज अगर कोई सच में आतंक फैला रहा है, तो वह है इंसानी लालच और विकास का अंधा मॉडल।

प्राकृतिक आवासों पर हमला

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ जैव विविधता की अद्भुत संपदा है। लेकिन यही भारत आज अपने ही जंगलों को खा रहा है। 2021 की Forest Survey of Iefdis रिपोर्ट बताती है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 1,100 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनक्षेत्र खो दिया है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में यह गिरावट विशेष रूप से चिंताजनक रही है। वन कटान केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है। यह पूरी एक पारिस्थितिकी व्यवस्था का ध्वंस है। जब हम पेड़ काटते हैं, हम न सिर्फ ऑक्सीजन के स्रोत मिटाते हैं, बल्कि हजारों पशु-पक्षियों के घर उजाड़ देते हैं। यही कारण है कि आज हमें गाँवों और शहरों के आसपास बाघ, हाथी, भालू और यहाँ तक कि तेंदुए भी दिखने लगे हैं।

शहरों में जानवरों की बढ़ती उपस्थितिः एक चेतावनी

बंदरों का शहरों में आना आज एक आम दृश्य बन गया है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, और देहरादून जैसे शहरों में बंदरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। कारण स्पष्ट हैं–कम होती हरियाली, अधिक होता कूड़ा, और बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन। इसी तरह, आवारा कुत्तों की संख्या भी शहरों में नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। WHO के अनुसार भारत में लगभग 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं,

और हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। मगर यह समस्या केवल स्वास्थ्य या सुरक्षा की नहीं है; यह समस्या हमारे कुप्रबंधन और लापरवाह विकास की है। हमने कूड़ा फेंकने के तरीकों को सुधारा नहीं, सार्वजनिक पशु-नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं दी, और अब जब जानवर हमारी बस्तियों में दिखते हैं, तो उन्हें संकट कह कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं।

मीडिया की भूमिका-भाषा का प्रभाव

जब कोई अखबार लिखता है कि बंदरों का आतंक, तो वह केवल सूचना नहीं दे रहा होता, बल्कि एक धारणा गढ़ रहा होता है। यह धारणा कि जानवर आक्रमणकारी हैं, और हम पीड़ित। मीडिया की यही भाषा यह छिपा लेती है कि असल में हम ही उनके घरों में घुसे थे, उनकी जमीन छीनी, और अब जब वो अपनी जगह पाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दोषी ठहराते हैं। यह भाषा केवल संवेदनहीन नहीं, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे संरक्षण के प्रति समाज की समझ और सहानुभूति दोनों कमजोर पड़ती हैं।

वन्यजीव संघर्षः क्यों बढ़ रहा है?

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 100 से अधिक लोग हाथियों के हमलों में मारे जाते हैं, और दर्जनों बाघ-मानव संघर्ष की घटनाएँ सामने आती हैं। मगर इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई यह है कि वन्यजीवों का घर सिकुड़ता जा रहा है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी उन्हें मानव बस्तियों की ओर खींचती है। कभी-कभी वे रास्ता भटक जाते हैं, तो कभी उन्हें मजबूरी में खेतों और घरों में घुसना पड़ता है। यह संघर्ष उनके लिए भी घातक है–हर साल सैकड़ों जानवर इंसानी जवाबी हिंसा में मारे जाते हैं।

क्या हो सकता है समाधान?

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे सशक्त कानून हैं, लेकिन उनके लागू करने में अनेक समस्याएँ हैं। वन विभाग अक्सर संसाधनों और जनबल की कमी से जूझता है। इसके अलावा, जब विकास परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण में टकराव होता है, तो अक्सर विकास को तरजीह दी जाती है, भले ही उसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हों। इस संकट से उबरने के लिए केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन जरूरी है। कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं: शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए – पार्क, बाग-बगिचे, और वृक्षारोपण को केवल सजावटी पहलू नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी के हिस्से के रूप में देखा जाए। वन्यजीव गलियारे (वन्यजीव गलियारे) विकसित किए जाएँ – जिससे जानवरों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिले। कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए – ताकि जानवर शहरी कूड़े पर निर्भर न हों। मीडिया और शिक्षा में संवेदनशीलता लाई जाए – जानवरों को 'आतंकवादी' बताने के बजाय उनके संघर्ष को समझने और सहानुभूति की भाषा अपनाई जाए। स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए – उन्हें संरक्षण के साझेदार बनाना होगा, विरोधी नहीं।

अंतिम बातः इंसान अकेला नहीं है इस धरती पर

हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह धरती केवल हमारी नहीं है। जंगलों, नदियों, पहाड़ों, और समंदरों के साथ-साथ हर जीव-जंतु का इस पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। जब हम शहरों का विस्तार करते हैं, जब हम मॉल और एक्सप्रेसवे बनाते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी की जमीन छीनी जा रही है–कभी किसी हिरन की, कभी किसी हाथी की। हम अगर प्रकृति से लड़ते रहेंगे, तो अंततः हार हमारी ही होगी–क्योंकि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता, बस अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है। बंदरों का आतंक एक समाचार की हेडलाइन हो सकती है, लेकिन असल हेडलाइन यह होनी चाहिए थी–जंगलों पर इंसानों का आतंक। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जरूरी है। अगर हम वास्तव में एक संतुलित, सुरक्षित और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति से नहीं, अपने अहंकार से संघर्ष करना होगा।

सम्पादकीय

उच्च शिक्षा में व्यावहारिक सुधारों की आवश्यकता है

शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और स्थिरता की गारंटी के लिए प्रभावी नीतिगत ढांचे आवश्यक हैं, जो राष्ट्र की उन्नति की नींव के रूप में कार्य करते हैं। फिर भी, चिकित्सा और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में अक्सर पुराने और कठोर नियमों के बजाय उनके द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई) मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए मनमाने मापदंड और निजी संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतन विनियम इस बात के उदाहरण हैं कि नौकरशाही की कठोरता के परिणामस्वरूप अनपेक्षित परिणाम कैसे हो सकते हैं। इन चिंताओं को हल करने और अधिक समावेशी और कुशल शिक्षा प्रणाली की खेती करने के लिए, व्यावहारिक नीति सुधारों को लागू करना अनिवार्य है।

विजय गर्ग
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

एमसीआई को मान्यता के लिए एक निश्चित संख्या में अस्पताल के बिस्तर और रोगी भार की आवश्यकता होती है। हालांकि लक्ष्य छात्रों को नैदानिक अनुभव देना है, यह रणनीति चिकित्सा शिक्षा विकास की अनदेखी करती है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, सिमुलेशन-आधारित शिक्षण और टेलीमेडिसिन छात्रों को बिस्तर-रोगी अनुपात के बिना व्यावहारिक कौशल विकसित करने की अनुमति देते हैं। मौजूदा कानूनों ने निरीक्षण के आंकड़ों में हेरफेर करने वाले संस्थानों जैसी बेईमान गतिविधियों का नेतृत्व किया है। बुनियादी ढांचे पर आधारित आकलन के बजाय, चिकित्सा शिक्षा नीतियों को योग्यता-आधारित मूल्यांकन, परिणाम-संचालित सीखने और नैतिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। आधुनिक शैक्षणिक सफलताओं को स्वीकार करने से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार होगा। आदर्श रूप से, सरकारों और चिकित्सा नियामक निकायों को बेहतर पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण और जीवन शैली जागरूकता के माध्यम से रोगों के बोझ को कम करके निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी, चिकित्सा शिक्षा में एक उच्च रोगी के बोझ की आवश्यकता निवारक दृष्टिकोण के बजाय एक प्रतिक्रियाशील का अर्थ है, एक जो लगातार या बीमार आबादी का विस्तार करता है। यदि समाज बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की दिशा में वास्तविक प्रगति करता है, तो यह मानदंड संभावित रूप से मेडिकल कॉलेजों की मान्यता बनाए रखने की क्षमता को बाधित कर सकता है। यह महत्वपूर्ण पूछताछ का संकेत देता है: **क)** क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं जो कल्याण के बजाय बीमारी पर कब्जा कर लेती है? **ख)** क्या केवल अस्पताल के रोगी की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निवारक देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और उन्नत तकनीक को प्राथमिकता देने के लिए चिकित्सा शिक्षा का पुनर्गठन करना आवश्यक है? एक प्रगतिशील चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को अधिक भीड़ के बजाय अस्पतालों में प्रवेश करने से रोकना होना चाहिए। कम रोगी गणना के लिए दंडित किए जाने के बजाय, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होने पर चिकित्सा संस्थानों को अनुकूलित करना चाहिए। एक और त्रुटिपूर्ण विनियमन यूजीसी का आग्रह है कि निजी संस्थान संकाय के लिए सरकारी वेतन तराजू का पालन करते हैं। यद्यपि शिक्षकों को समान मुआवजे के साथ प्रदान करना अनिवार्य है, लेकिन वित्तीय सहायता प्रदान किए बिना निजी संस्थानों में सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन संरचनाओं को लागू करना इन संस्थानों पर अत्यधिक बोझ डालता है। निजी विश्वविद्यालयों को ट्यूशन फीस बढ़ाने, कई छात्रों के लिए शिक्षा को अस्थिर करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से ट्यूशन राजस्व पर भरोसा करते हैं। इसी तरह, विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए एक शर्त के रूप में 40 एकड़ भूमि पर आग्रह आज के डिजिटल युग में एक पुराना और अव्यावहारिक विनियमन है। ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल लैब, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमुखता मिलने के साथ, विशाल भौतिक परिसरों की पारंपरिक अवधारणा कम प्रासंगिक होती जा रही है।

जजों की संपत्ति का प्रकटीकरण पारदर्शिता की ओर कदम

-ललित गर्ग- | लेखक

न्यायपालिका पर जनता का भरोसा लोकतंत्र का अहम आधार है। न्यायिक प्रणाली में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता, जबावदेही एवं निष्पक्षता की जरूरत है, इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतों तक के न्यायाधीशों को संपत्ति सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाए जाने की अपेक्षा आजादी के अमृतकाल में तीव्रता से की जा रही थी, ताकि न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले संदेह दूर हो सकें, यह मुद्दा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर जली हुई नोटों की गड्डी मिलने जैसी घटनाओं और उनसे उपजे विवादों के बाद गंभीर सार्वजनिक विमर्श का बन गया था। जनचर्चाओं एवं आदर्श राष्ट्र-निर्माण की अपेक्षाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने पर जो सहमति जताई है, वह सही दिशा में उठाया गया उचित एवं प्रासंगिक कदम है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का उस पर भरोसा मजबूत होगा। देश में न्यायालयों को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है, जो आम लोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद है। न्याय करने वाले न्यायाधीशों पर संदेह के बादल मंडराना न्याय-प्रक्रिया पर भरोसा कम करने का एक बड़ा कारण बनता रहा है। अब जनता की अपने पंच-परमेश्वरों की स्वच्छ-धवल छवि की आकांक्षा पूरी होते हुए दिखाई देना एक रोशनी बना है, जिससे न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास ज्यादा मजबूत होगा।

ग्लोबल हेराल्ड

नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी ही चाहिए। न्यायधीशों को भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार हर न्यायाधीश को अपनी प्रॉपर्टी और देनदारियों के बारे में चीफ जस्टिस को बताना होता है। बाद में, एक और प्रस्ताव आया कि न्यायाधीश चाहें तो अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक था। पिछले लगभग तीन दशक में, यह मामला कई बार उठा है। सूचना का अधिकार लागू होने के बाद यह बहस भी हुई कि न्यायपालिका इसके दायरे में क्यों नहीं? इसके पीछे यही तर्क रहा कि किसी निजी जानकारी को तब तक साझा करने की जरूरत नहीं, जब तक उससे सार्वजनिक हित न जुड़े हों। 2010 और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब इसी तथ्य को आधार बनाकर कहा गया कि जानकारी सार्वजनिक करना न्यायाधीशों की इच्छा पर है। एक तरह से यह व्यवस्था न्यायाधीशों को लगातार संदेहों के घेरे में रखती रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता कायम करने वाला एक सराहनीय कदम होगा। जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग के पीछे बड़ा तर्क भी यही दिया जाता रहा है कि जब तक जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं होगी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठोस कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज, सरल पारदर्शी एवं समानतामूलक होने के साथ आम आदमी के भरोसे वाली होनी चाहिए। इसके लिये भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण के लिये ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जबावदेही आवश्यक मूल्य है।

सरकार की एक संसदीय समिति ने 2023 में सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य की जाए। हालांकि कतितय कारणों से सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ी। इसका एक बड़ा कारण सरकार पर यह आरोप लगना भी बना कि सरकार न्यायपालिका में अनावश्यक राजनीतिक दखल दे रही है। लेकिन न्यायपालिका की साख के लिए उसका स्वतंत्र होना और दिखना भी जरूरी है। लेकिन सम्पत्ति की घोषणा के मामले में उन्हें अतिरिक्त सुविधा देना या उनके लिये अतिरिक्त सुविधा का होना, संदेह का कारण बनता रहा है। दरअसल, वर्तमान परिपाटी के अनुसार न्यायाधीशों के लिये निजी संपत्ति का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना एक स्वैच्छिक परंपरा है। जिसे अनिवार्य बनाने की मांग की जाती रही है। निश्चय ही न्याय व्यवस्था के संरक्षक होने के कारण इसके स्वैच्छिक रहने पर तमाम किंतु-परंतु हो सकते हैं। यूं तो न्यायपालिका के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। संपत्ति की घोषणा जैसे कई स्तरों पर न्यायिक सुधार के प्रयास आगे बढ़ाने की जरूरत नये भारत, सशक्त भारत एवं आदर्श भारत के लिये जरूरी है। अब अगर सर्वोच्च अदालत के जज खुद को भी उन कसौटियों पर कसने में नहीं हिचक रहे हैं जिन्हें वे दूसरों के लिए जरूरी मानते हैं, तो निश्चित ही इस कदम से एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है। न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट के सभी 30 मौजूदा न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से प्रकट करने पर सहमति व्यक्त की है। यह घटनाक्रम न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद हुआ है, खासकर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद के बाद। जिन न्यायाधीशों ने पहले ही अपनी घोषणाएं प्रस्तुत कर दी हैं, उनमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी शामिल हैं। इसे फैसले को न्याय के प्रति जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिहाज से सही एवं सामयिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सुखद होने के साथ-साथ श्रेयस्कर न्याय-प्रक्रिया का द्योतक है। निश्चय ही यह एक सार्थक पहल ही कही जाएगी। इस नवीनतम प्रस्ताव के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक रूप से संपत्ति के खुलासे को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने का निर्णय लेकर जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत के अनेक पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि में न्यायाधीश अपनी संपत्तियों की घोषणा करते हैं। कई देशों में यह स्वैच्छिक है तो कुछ जगह अनिवार्य भी है। न्यायपालिका ही फरियाद का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बल्कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायाधीश अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें तो इससे जनता को उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा। अब तक का अनुभव बताता है कि उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी जजों में संपत्ति को सार्वजनिक करने की प्रवृत्ति काफी कम है। मार्च 2025 तक, उच्च न्यायालयों के कुल 763 में से सिर्फ 49 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अभी इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा करना कानूनन अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में आम जनमानस में धारणा बनी रहती है कि न्यायपालिका के बाबत भी कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रश्न न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और जबावदेही से भी जुड़ा है। यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि विधि एवं न्याय विभाग की संसदीय समिति ने वर्ष 2023 में न्यायाधीशों के लिये अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा की सिफारिश की थी। लेकिन इस बाबत अभी तक कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अब स्वयं न्यायपालिका की तरफ से ऐसी व्यवस्था लागू करने का सराहनीय प्रयास होना सुखद ही कहा जायेगा। न्यायपालिका हमेशा से समाज में पारदर्शिता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता व शुचिता की पक्षधर रही है। जनता इस कसौटी पर अपने न्याय के देवताओं को भी खरा उतरता देखना चाहती है। निस्संदेह इस तरह के फैसले का समाज में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से दूरगामी प्रभाव भी होगा।

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

भारत में लग सकता है आर्थिक आपातकाल

भारत में जिस तरह की आर्थिक स्थिति वित्तीय संस्थानों की बन रही है। उसको देखते हुए आर्थिक आपातकाल लागू करने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के टेरिफ बार के बाद सारी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वैश्विक आर्थिक मंदी की बात सामने आने लगी है। भारतीय शेयर बाजार की गिरावट को रोकने पिछले 6 महीने से सरकार ने जितना भी प्रयास किया। उसके बाद भी शेयर बाजार को गिरने से रोकने में सरकार की कोई मदद नहीं मिली। सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। जिसके कारण करीब 16 लाख करोड रुपए का नुकसान एक ही दिन में शेयर बाजार में हो गया है। बैंकों की स्थिति भी शेयर बाजार के कारण डंवाडोल हो रही है। सरकार ने शेयर बाजार को गिरने से रोकने के लिए कई बार भारत के वित्तीय संस्थानों ने बहुत बड़ा निवेश भारतीय शेयर बाजार में किया है। शेयर बाजार की गिरावट के कारण बैंक अंदर से खोखले हो चुके हैं। भारत के कुछ बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी तथा बाजार में घटती मांग के कारण उद्योग व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों पर भारी कर्ज है। सरकार ने खजाने का 20 से 30 फीसदी राजस्व कर्ज और ब्याज को अदायगी के लिये हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, देश में पहली बार आर्थिक आपातकाल घोषित कर सकती है। भारत में पहिले तीन बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। यह तीनों आपातकाल बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाए गए थे। आर्थिक विशेषज्ञ यह आशंका व्यक्त करने लगे हैं। भारत में सरकार कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकती है। आर्थिक आपातकाल लगा होने पर 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से सरकार को मंजूरी लेनी होती है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद आर्थिक आपातकाल को लंबे समय तक लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान में कोई अवधि तय नहीं है। इसे रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में तीन कारणों से आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों के लिये आपातकाल अनुच्छेद 356 तथा आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। आर्थिक आपातकाल वित्तीय अस्थिरता या साख को गंभीर खतरा होने पर लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों का नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। आर्थिक आपातकाल की घोषणा तभी हो सकती है। जब वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो जाता है। अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने पर केंद्र को आपातकाल के जरिये विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार किसी भी राज्य में वित्तीय हस्तक्षेप कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान सभी धन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्य के धन पर केंद्र का अधिकार हो जाता है। वित्तीय आपातकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है। एक बार संसद से आपातकाल बिल पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसे खत्म कर सकते हैं। जिस तरह की आर्थिक स्थिति देखने को मिल रही है। उसके बाद आर्थिक विशेषज्ञों को यह आशंका दिखने लगी है। भारत में जल्द ही आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है। पिछले 75 सालों में कभी भी आर्थिक आपातकाल भारत में नहीं लगा है। आर्थिक आपातकाल लागू हुआ, तो यह एक नया रिकॉर्ड होगा केंद्र एवं राज्य सरकारों को समय रहते देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनानी होंगी। जिस तरह से शेयर बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है। उसका असर भारतीय बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ना तय है। उसके कारण आर्थिक आपातकाल की आशंका को बल मिल रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं बंद हो सकती हैं। कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। सरकार केवल जरूरी खर्चों के लिए ही राशि खर्च कर सकती है। राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। भारत में यह स्थिति पहली बार बन रही है। मंहगाई और बेरोजगारी को देखते हुए आर्थिक अनुशासन बनाने के लिये आपातकाल ही एकमात्र सहारा आर्थिक विशेषज्ञ देख रहे हैं।

सनत जैन
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

सच्चे ज्ञानी की विशेषता

व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को-शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को- एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता को संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं।

कभी-कभी संस्कृत शब्द परमेर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं। वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। जीव, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आपको नीचे नहीं गिराता, और इसीलिए वह प्रमशः वैकुण्ठ-लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रियतृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। यह शरीर परमात्मा के निदेर्शानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है।

ग्लोबल हेराल्ड में प्रकाशित होने वाले लेख लेखकों के निजी विचार है

व्यापार

इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल ने दिखाया दम, हरे निशान पर बंदा हुआ बाजार

मुंबई ■

एशियाई बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और एलएंडटी जैसे भारी भरकम स्टॉक्स में जोरदार तेजी से बाजार हरे निशान पर बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार के कारोबार में 900 से ज्यादा अंक चढ़कर 74,013.73 पर खुला। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 74,859 अंक तक उछला था। अंत में सेंसेक्स 1089.18 अंक के जोरदार उछाल के साथ 74,227.08 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई (एनएसई) का निफ्टी-50 भी मंगलवार को मजबूती के साथ 22,446.75 अंक पर खुला। खुलते ही बाजार में जोरदार तेजी

देखी गई। कारोबार के दौरान यह 22,697.20 अंक को छू गया। अंत में निफ्टी 374.25 अंक की मजबूती के साथ 22,535.85 पर बंद हुआ। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने चीन पर दबाव बढ़ाते हुए चीन से रेसिप्रोकल टैरिफ वापस लेने की बात कही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन ट्रंप की रणनीति के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहने की तैयारी में है। वहीं जापान का निक्केई इंडेक्स मंगलवार को औसत रूप से 6 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। यह पिछले सत्र में 1-1/2 साल के निचले स्तर से उबरा। निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट पर रिकवरी के संकेतों से उत्साहित होकर शेयरों को खरीदा। निक्केई इंडेक्स 6.03 प्रतिशत चढ़कर 33,012.58 पर पहुंच गया, जो 6 अगस्त के बाद से इसका सबसे तेज एक दिवसीय लाभ है।

आरबीआई के ब्याज दरों पर फैसले का इंतजार

वैश्विक बाजारों की चाल के अलावा निवेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो बुधवार को निर्धारित है। साथ ही भारतीय कंपनियों के चौथे तिमाही के नतीजे और इस सप्ताह आने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों पर भी निवेशकों का फोकस है।

सोने और चांदी के भाव में आया उछाल

नई दिल्ली ■

वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं में तेजी की वजह से देशा के सराफा बाजारों में भी सोने-चांदी के भाव में मंगलवार को तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में आज दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 87,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे, जबकि चांदी के भाव 89,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क जून कॉन्ट्रेक्ट 631 रुपये की तेजी के साथ 87,559 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 86,928 रुपये था। इस समय यह 507 रुपये की तेजी के साथ 87,435 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 87,576 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 87,380 रुपये के भाव पर

दिन का निचला स्तर छू लिया। सोने के वायदा भाव ने इस महीने 91,423 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मई कॉन्ट्रेक्ट 650 रुपये की तेजी के साथ 88,898 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 88,248 रुपये था। इस समय यह 794 रुपये की तेजी के साथ 89,042 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 89,088 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 88,799 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 1,01,999 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था।

वेदांता को वैश्विक साझेदार की तलाश

नई दिल्ली। खनन कंपनी वेदांता विभिन्न क्षेत्रों में अपनी 20 अरब डॉलर की विस्तार परियोजनाओं के लिए वैश्विक साझेदार की तलाश कर रही है। कंपनी के अनुसार यह कदम वेदांता की रणनीतिक योजना के अनुरूप है जिसके तहत अगले तीन वर्षों में वह अपने परिचालन का महत्वपूर्ण विस्तार करेगी। इसके तहत कंपनी अपने कारोबार का चार इकाइयों वेदांता एल्युमीनियम, तेल एवं गैस, बिजली और लोहा एवं इस्पात में पुनर्गठन करेगी। जानकारी के अनुसार हम एक अनुभवी वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसे इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण प्रबंधन (ईपीसीएम) में अनुभव हो और जो हमारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमारे लिए एक विस्तारित कार्यालय के रूप में कार्य कर सके। कंपनी ने कहा कि वह अगले तीन वर्षों में धातु, खनन और हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं पर 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी।

मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री में छह प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली ■

भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 2,61,43,943 इकाई हो गई है। यह जानकारी वाहन डीलरों के एक संगठन ने सोमवार को जारी एक बयान में दी। बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रहा।

वाहन डीलरों के संगठन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण बाजारों में दोपहिया वाहनों की बिक्री में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शहरी क्षेत्रों से अधिक है। इसके साथ ही तिपहिया वाहनों की ग्रामीण बिक्री में नौ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वाइन डीलर संगठन के अध्यक्ष ने बयान में बताया कि मोटर वाहनों के खुदरा क्षेत्र में मजबूती देखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। वाहनों की बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़ोतरी होने की खबर भविष्य में स्थिरता की ओर इशारा कर सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा ?कि वित्त वर्ष 2024-25 ने वास्तव में दिखाया कि भारत का मोटर वाहन खुदरा क्षेत्र कितना लचीला हो सकता है, इस वर्ष मुख्य आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन रहा। दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में ग्रामीण बाजारों में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शहरी क्षेत्रों की वृद्धि से काफी अधिक है। यात्री वाहन क्षेत्र में ग्रामीण बिक्री वृद्धि आठ प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में यह तीन प्रतिशत रही।

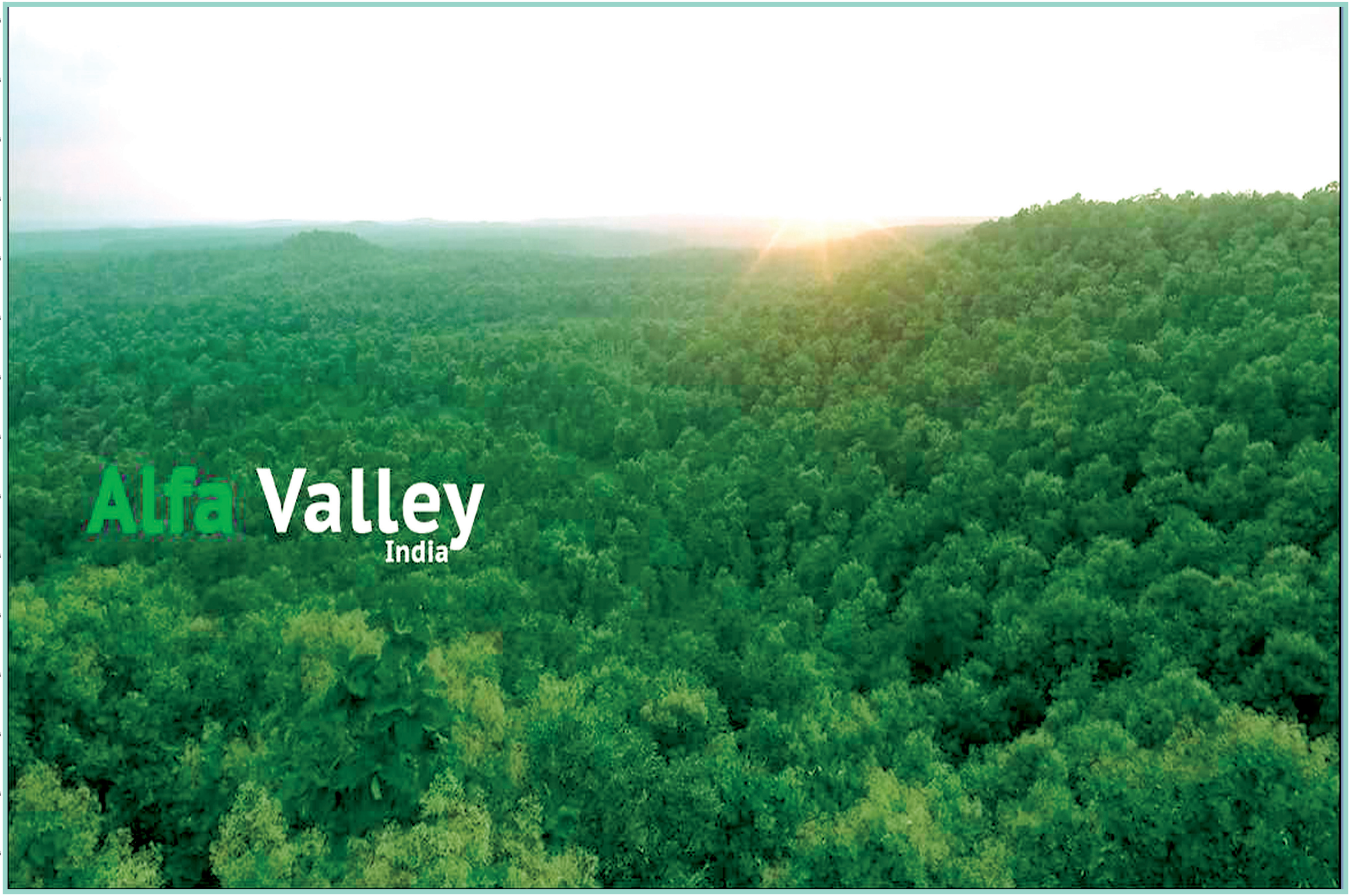

Alfa Valley
India

मनोरंजन

रश्मिका मंदानाः छोटे शहर की लड़की से भारत की सुपरस्टार बनने तक का प्रेरणादायक सफर

रश्मिका मंदाना का नाम आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सफलता, मेहनत और समर्पण का पर्याय बन चुका है। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के एक छोटे से कूर्ग शहर से निकली इस लड़की ने सपनों की दुनिया में न केवल कदम रखा, बल्कि उसे अपने नाम भी किया। 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई, और तभी से उनके लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल नहीं रहा। रश्मिका ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों के ज़रिए खुद को एक भरोसेमंद अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पाः द राइज़, जिसमें उन्होंने श्रीवल्ली का किरदार निभाकर देशभर में लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। फिल्म का गाना सामी सामी रश्मिका के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें पूरे भारत में एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया। दक्षिण से बॉलीवुड तक का सफर भी उन्होंने उतनी ही सफलता से तय किया। अमिताभ बच्चन के साथ गुडबाय से हिंदी फिल्मों में कदम रखने के बाद, रणबीर के साथ फिल्म एनिमल में उन्होंने जबरदस्त अभिनय कर दर्शकों को चौंका दिया।

को-एक्टर की एक्साइटमेंट पूरी तरह से हावी हो गई थीः अनुप्रिया गोयनका

हाल ही में इंटीमेट सीन के दौरान बालीवुड एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका ने अपने साथ हुई एक असहज घटना का खुलासा किया। अनुप्रिया ने बताया कि कैसे एक बार उनके को-एक्टर ने शूटिंग के दौरान अपनी एक्साइटमेंट के चलते उन्हें असहज महसूस कराया। मीडिया से चर्चा में अनुप्रिया गोयनका ने बताया, यह घटना दो बार हुई। एक बार मैं नहीं कह सकती कि वह व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा था, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट पूरी तरह से हावी हो गई थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा, मैं देख सकती थी कि वह एक्साइटेड हो रहा था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति बनती है, तो आप अपमानित और असहज महसूस करते हैं। यह सब किसिंग सीन के दौरान हुआ था। अनुप्रिया ने एक और किस्सा सुनाते हुए बताया, मैंने उस दिन ऐसे कपड़े पहने थे जो आरामदायक नहीं थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे को-एक्टर को पता होगा कि ऐसे सीन के दौरान महिला को कमर से पकड़ना सही होता है, लेकिन उन्होंने मेरे बट्स (हिप) पर दोनों हाथ रख दिया। जबकि, वह मेरी कमर को पकड़ सकते थे। अनुप्रिया ने बताया, बाद में मैंने धीरे से उनके हाथों को ऊपर (कमर तक) ले जाकर कहा कि इन्हें यहीं पर रखें, नीचे नहीं। लेकिन उस समय मैं उनसे यह नहीं पूछ पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं सोच रही थी कि वह बस कह सकते थे कि यह गलती से हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगले टेक में इसे सही तरीके से करना। एक्ट्रेस ने कहा कि वह उस वक्त सीधे तौर पर इस मुद्दे को नहीं उठा पाईं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को-एक्टर से साफ तौर पर कहा कि अगली बार ऐसा न हो और उन्हें सही तरीके से सीन करना चाहिए।

कॉमेडियन अपूर्वा मखीजा ने हटाए सभी पोस्ट

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन अपूर्वा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। अपूर्वा मखीजा ने न केवल अपनी पोस्ट हटाईं, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर सभी को अनफॉलो भी कर दिया। उनके इस अचानक लिए गए फैसले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इसे हाल ही में हुए विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उनके 30 लाख से अधिक फॉलोअर्स अभी भी बरकरार हैं। फरवरी में अपूर्वा मखीजा ने कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में जज की भूमिका निभाई थी। यह शो तब विवादों में आ गया जब रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता और सेक्स से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के बाद मुंबई में कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें शो से जुड़े अन्य कलाकारों, अपूर्वा मखीजा और समय रैना सहित कई सोशल मीडिया हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मखीजा पर भी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें मुंबई पुलिस के समक्ष पेश होना पड़ा था।

कोलकाता घर में लगातार दूसरा मैच हारीःलखनऊ ने 4 रन से हराया, पूरन ने नाबाद 87 रन बनाए, मार्श की फिफ्टी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 4 रन की रोमांचक जीत हासिल की है। यह कोलकाता की उसके घरेलू मैदान पर लगातार दूसरी जीत है। टीम को पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 विकेट से हराया था। मंगलवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 239 रन का टारगेट चेज कर रही कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 234 रन ही बना सकी। रिंकू सिंह 15 बॉल पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे।

कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 61 और वेंकटेश अय्यर ने 45 रन बनाए। दोनों ने 40 बॉल पर 71 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी टूटते हुए कोलकाता की टीम बिखर गई। आकाश दीप और शार्दूल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। टॉस हारकर बैटिंग कर रही लखनऊ ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 238 रन बनाए। निकोलस पूरन 36 बॉल पर 87 रन बनाकर नाबाद बनाए। मिचेल मार्श ने 81 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। ऐडन मार्करम ने 47 रन बनाए। हर्षित राणा ने 2 विकेट झटके। एक विकेट आंद्रे रसेल को मिला।

दोनों टीमों की प्लेइंग- 11

कोलकाता नाइट राइडर्सः अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा। इम्पैक्ट प्लेयरः अंगकृष रघुवंशी।

लखनऊ सुपर जाएंट्सः ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मिचेल मार्श, ऐडन मार्करम, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दूल ठाकुर, दिग्वेश राठी, आवेश खान और आकाश दीप। इम्पैक्ट प्लेयरः रवि बिश्नोई।

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने भुवनेश्वर

नई दिल्ली ■ एजेंसी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए आईपीएल में खेल रहे भुवनेश्वर कुमार ने एक इतिहास रच दिया है। भुवनेश्वर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में भुवनेश्वर ने वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ दिया है, जो लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट रहे थे। अब वे आईपीएल में नहीं खेलते हैं।

भुवनेश्वर को सोमवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में एक विकेट मिला। भुवनेश्वर ने तिलक वर्मा को आउट किया और इसके साथ वे आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बन गए। भुवनेश्वर ने 179वें मैच में 184वां विकेट आईपीएल में लिया। इससे पहले ब्रावो ने 161 मैचों में 183 विकेट अपने नाम किए थे। भुवनेश्वर ने मुंबई के खिलाफ 4 ओवर में 48 रन दिए, लेकिन 18वें ओवर में तिलक को आउट करके उन्होंने आरसीबी की जीत पक्की कर दी थी। आईपीएल में बतौर तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब भुवनेश्वर के नाम है, जबकि सूची में दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो हैं और तीसरे नंबर पर लसिथ मलिंगा हैं, जिन्होंने 122 मैचों में 170 विकेट लिए थे। वहीं, जसप्रीत बुमराह का चौथे नंबर पर आते हैं। वे 134 मैचों में 165 विकेट अब तक ले चुके हैं। वहीं, पांचवें नंबर पर उमेश यादव हैं। उमेश ने 148 मैचों में 144 विकेट लिए हैं।

धोनी ने पसंदीदा टीम में सचिन सहित 3 खिलाड़ियों को ही रखा

मुम्बई ■ एजेंसी

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने अपने करिकर में कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेल और टीम की कप्तानी भी की पर जब धोनी से उनके पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तीन नाम ही बताये। इसमें धोनी ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ ही आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया है।

धोनी ने अपने करियर में जहीर खान, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ खेला। इसके अलावा अपने 16 साल के करियर में धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी निखारा। वहीं जब धोनी से अपनी पसंदीदा टीम चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने केवल तीन भारतीय खिलाड़ियों को ही शामिल किया। इसके बाद उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। धोनी ने कहा, हां, मैं अपने भारतीय खिलाड़ियों के साथ रहूंगा। सहवाग , सचिन, गांगुली क्योंकि, आप जानते हैं, बात यह है कि हर किसी को अपने शीर्ष पर रखकर पर कल्पना करें और ऐसे में जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, तो आपको लगेगा कि उनसे बेहतर कोई नहीं है जबकि क्रिकेट उतार-चढ़ाव का खेल है। इसलिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे चुनें लेकिन बड़े होकर हम सभी ने इन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते देखा है।

बिली जीन किंग कप से पहले भारत की अंकिता रैना ने कही यह बात, टीम के बीच दिया बयान

पुणे ■ एजेंसी

भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने मंगलवार से शुरू हो रहे बिली जीन किंग कप एशिया-ओशिनिया ग्रुप-1 से पहले बयान दिया है। उन्होंने आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि टीम के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। अंकिता ने कहा कि अब इस पल का आनंद लेने का समय है। देश की नंबर एक खिलाड़ी अंकिता इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कमान संभालेगी।

उनके अलावा सहजा यमलापल्ली, श्रीवल्ली भामिदिपति, वैदेही चौधरी और युगल विशेषज्ञ प्रार्थना थोम्बरे भी टीम का हिस्सा हैं। 15 साल की माया राजेश्वरन रिजर्व खिलाड़ी हैं, जबकि पूर्व डेविस कप खिलाड़ी विशाल उप्पल कप्तान और राधिका कानिटकर तुलपुले कोच हैं। अंकिता ने कहा, हर कोई टूर्नामेंट का इंतजार कर रहा है और मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। टीम के बीच तालमेल बहुत अच्छा है और हम शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। मैं बस उन्हें (युवा खिलाड़ियों को) यही कह रही हूं कि आप देश के लिए खेल रही हो और इसका पूरा आनंद लो। मैं उनसे कहूंगी की अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इस मुकाम तक पहुंचना बहुत से लोगों का सपना होता है। इसलिए बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, वहां हर पल का आनंद लें। परिणाम के बारे में चिंता न करें। भारत शुरुआती दिन न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। मंगलवार को अन्य मैचों में कोरिया चीनी ताइपे से और थाईलैंड हांगकांग से भिड़ेगा। न्यूजीलैंड के बाद भारतीय टीम राउंड-रॉबिन ग्रुप में चीनी ताइपे, कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग और चीन से भिड़ेगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें प्लेऑफ चरण में जगह बनाएंगी।

पैन इंडिया लेवेल पर 10 अप्रैल को रिलीज हो रही जाट

आगामी 10 अप्रैल को अभिनेता सनी देओल की फिल्म जाट पैन इंडिया लेवेल पर रिलीज हो रही है। जाट को टॉलीवुड डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में गोपीचंद ने कई तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह प्रभास और सनी के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। गोपीचंद ने बताया कि प्रभास ने 'जाट' की शूटिंग सेट पर जाकर सनी देओल और फिल्म की यूनिट से मुलाकात की थी। एक तस्वीर में प्रभास और सनी देओल साथ में फोटो के लिए पोज दे रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए गोपीचंद ऐसा कमेंट किया है, जिस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। गोपीचंद मलिनेनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जब बाहुबली और जाट मिलते हैं, तब एक मैसिव फ्रेम बनता है। एक्शन सिनेमा के दो आइकन। रेबेल स्टार प्रभास, एक्शन सुपरस्टार सनी देओल और डायरेक्टर गोपीचंद जाट के सेट पर।

रिंकू ने टेटू का राज बताया

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बांह में बनाये टेटू का राज बताया है। रिंकू ने कहा कि इससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गयी। रिंकू ने अपने क्रिकेट के सफर को याद करते हुये इस टैटू को लेकर बताया जिस पर 'भगवान की योजना, खूबसूरती से लिखा हुआ था और साथ ही '2:20 लिखा हुआ था। ठीक वही पल जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े और उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गयी। तक रिंकू ने लगातार पांच गेंदों में छक्के लगाये थे और वह रातों रात स्टार बन गये थे। कोलकाता फ्रेंचाइजी के साथ अपने विशेष संबंध को दिखने वाले इस टैटू की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे 2018 में केकेआर ने 80 लाख रुपये में खरीदा था, तो वह रकम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। तब पहले हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। परिवार की जिंदगी बदल गई। मेरे भाई-बहनों की शादियाँ आसान हो गईं, और हमने उस पैसे से एक घर भी खरीदा। इसलिए मैंने यह टैटू बनवाया है, जिस पर परिवार लिखा है। जब मुझे चुना गया, तो ठीक 2:21 या 2:20 का समय था और उस क्षण से सब कुछ बदल गया।

अब आप भी बन सकते हैं
ग्लोबल रिपोर्टर
अपने आस-पास होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां, घटना-दुर्घटना की खबर, फोटो या वीडियो हमें वाट्सएप करें
7999509078
ना केबल कनेक्शन की झंझट, ना ही सेट-टॉप बॉक्स का खर्चा
ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ अब IPTV पर भी
बस एक बार गूगल करें और देखें हमेशा ताज़ातरीन खबरें
www.globalheraldtv.com
ग्लोबल हेराल्ड NATIONAL HERALD
न्यूज़ पेपर न्यूज़ चेनल वेब टीवी
globalheraldeditor@gmail.com

LITTAL®
www.pramodmarutiparts.com

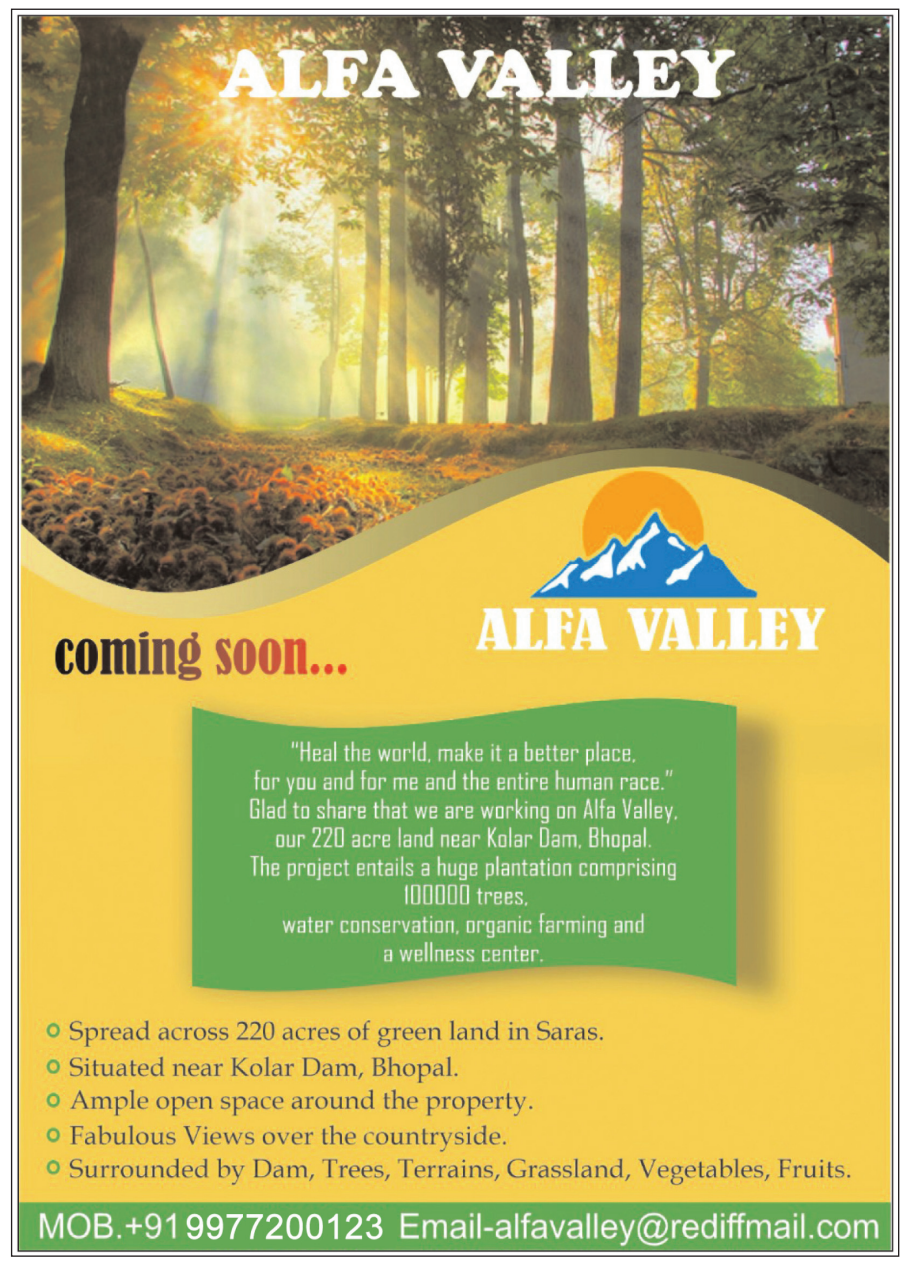

प्रकाशक एवं मुद्रक **विष्णु गोयल** द्वारा स्वामी शिवा पब्लिकेशन के लिए 1-ए, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स एबी रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित एवं पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रा.लि. रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, सेंटर पाइंट, मांगलिया बायपास, इंदौर, मध्यप्रदेश से मुद्रित। Epaper_www.globalherald.news
प्रधान संपादक -**विष्णु गोयल,** सलाहकार संपादक- **सौरभ बैनर्जी**, प्रदेश संपादक- **दिलीप शर्मा**, स्थानीय संपादक **सत्येन्द्र जैन** *(*समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार)। मोबाइल नं.:-7999509078, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2012/41876, email- editor@nationalherald.org/globalheraldeditor@gmail.com